www.vibhorvarta.com

R.N.I.No. UTTHIN/2009/29251

E-mail: vibhor.trikha@gmail.com

दैनिक

विभोर वार्ता

''मिथ्या से दूर सत्य के पास''

हरिद्वार

वीरवार, 3 जुलाई 2025

(बैशाख कृष्ण पक्ष सप्तमी, संवत 2073)

वर्ष: 17 अंक: 237

पृष्ठ: 8 मूल्य:1 रूपये

ऊधमसिंहनगर ■ देहरादून ■ हरिद्वार ■ चंडीगढ़ ■ मेरठ से एक साथ प्रकाशित

कांवड़ मार्ग में स्थित खाद्य की दुकान पर मालिक का नाम, लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना जरूरी:सीएम

बिना नाम और लाइसेंस वाली दुकानें होंगी बंद, धामी सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए जारी किए सख्त निर्देश

उत्तराखंड। श्रद्धा और आस्था के महापर्व कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर उत्तराखंड सरकार ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने एक सख्त और समर्पित कार्ययोजना तैयार की है, जिसके तहत लाखों श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए व्यापक निगरानी अभियान चलाया जाएगा।

कानूनी कार्रवाई व ध्2 लाख तक का जुर्माना- कांवड़ यात्रा 2025 के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए शासन ने सख्त व्यवस्था लागू कर दी है। स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ आर. राजेश कुमार ने कहा इस संबंध में यात्रा मार्गों पर मौजूद सभी होटल, ढाबा, ठेली, फड़ व अन्य खाद्य कारोबारियों को कुछ जरूरी निर्देश दिए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है, हर खाद्य कारोबारी को अपने लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक साफ-सुथरी प्रति अपने प्रतिष्ठान में प्रमुख जगह पर लगानी होगी, ताकि उपभोक्ता उसे आसानी से देख सकें।

छोटे व्यापारियों व ठेले-फड़ वालों को भी अपना फोटो पहचान पत्र और पंजीकरण प्रमाण पत्र अपने पास रखना और प्रदर्शित करना जरूरी होगा। होटल, भोजनालय, ढाबा और रेस्टोरेंट में 'फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड' भी साफ-साफ दिखाई देने वाले स्थान पर लगाया जाना चाहिए, जिससे ग्राहक को यह पता चल सके कि खाने की गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसकी है। जो कारोबारी ये निर्देश नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ध्2 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन हो। श्रद्धालुओं की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त खाद्य

(शेष पृष्ठ सात पर....)

आपदा प्रभावितों को बांटी 5.14 लाख की अहैतुक सहायता राशि

देहरादून(सू.वि.)। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर सदर तहसील के अंतर्गत दैवीय आपदा से प्रभावित 22 लोगों को 5.14 लाख की अहैतुक सहायता धनराशि के चेक वितरित किए गए। अतिवृष्टि के कारण मानव क्षति, कच्चे और पक्के भवन के आंशिक क्षति होने पर प्रभावितों को यह अहैतुक सहायता उपलब्ध कराई गई है।

(शेष पृष्ठ सात पर....)

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कार्मिकों का हुआ पहला रेन्डमाइजेशन

देहरादून(ब्यूरो)। जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी/नोडल अधिकारी कार्मिक अभिनव शाह की अध्यक्षता में 01 जुलाई को मतदान कार्मिकों का सॉफ्टवेयर के माध्यम से पहला रेंडमाइजेशन किया गया। इसमें जिले के 14 हजार पात्र कार्मिकों के पूर्ण डेटाबेस से 25 प्रतिशत रिजर्व सहित 7560

(शेष पृष्ठ सात पर....)

पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू, महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित

देहरादून(ब्यूरो)। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 2 जुलाई से औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। हरिद्वार जिले को छोड़कर सभी 12 जिलों में होने वाले इस चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 5 जुलाई तक चलेगी।

चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 7 से 9 जुलाई के बीच नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। पंचायत चुनाव इस बार दो चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होना है। जबकि मतगणना 31 जुलाई को कराई जाएगी।

बता दें प्रदेश के 89 ब्लॉकों की कुल 7499 ग्राम पंचायतों में पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इनमें ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए मतदान होगा। इस चुनाव में महिलाओं को बराबर का प्रतिनिधित्व देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।

जानकारी के लिए बता दें 7499 ग्राम प्रधान पदों में से 3772 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। प्रदेश में पंचायत चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था पहले से लागू है, जिसका असर इस बार भी व्यापक रूप से देखने को मिलेगा।

मेडिकल फैकल्टी के लिये बनेगी पृथक तबादला नीति

चिकित्सा शिक्षा विभाग में होगी शत-प्रतिशत नियुक्ति व प्रमोशन

देहरादून(ब्यूरो)। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में तैनात मेडिकल फैकल्टी के लिये पृथक स्थानांतरण नीति बनाई जायेगी। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुये नई स्थानांतरण नीति तैयार करने को कहा गया है। इसके अलावा विभाग में लम्बे समय से रिक्त पदों को भरा जायेगा साथ ही कार्मिकों को प्रमोशन का भी लाभ सुनिश्चित किया जायेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में हेल्थ नेटवर्क मजबूत करने के दृष्टिगत दूरस्थ व दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सकों के मानदेय में वृद्धि की जायेगी।

यह बात प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित 'डॉक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड-2025' कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कही।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये डॉ. रावत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में मजबूत स्वास्थ्य तंत्र विकसित करने में जुटी है। इसके लिये सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। जिनमें राजकीय चिकित्सालयों एवं मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ चिकित्सकों, चिकित्साधिकारियों, नर्सिंग अधिकारियों, पैरामेडिकल व तकनीकी स्टॉफ की बड़े पैमाने पर नियुक्ति की है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों एंव चिकित्सालयों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है।

डॉ. रावत ने कहा कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संकाय सदस्यों के स्थानांतरण के लिये पृथक से नीति बनाई जायेगी, जो मेडिकल फैकल्टी पर केन्द्रित होगी। नई नीति में पारदर्शी स्थानांतरण को लेकर स्पष्ट व्यवस्था होगी जिससे कार्मिकों को अपने स्थानांतरण लेकर कोई भ्रम न रहे। उन्होंने कहा कि नई स्थानांतरण नीति को तैयार करने से पहले विभागीय अधिकारियों को प्रत्येक पहलुओं का बारीकी से अध्ययन करने को कहा गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार राजकीय चिकित्सालयों व मेडिकल कॉलेजों में ढ़ांचागत व्यवस्था के साथ ही आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों के साथ ही आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों की व्यवस्था कर रही है। इसके अलावा विभागों में विभिन्न संवर्गों के तहत लम्बे समय से रिक्त पड़े पदों को भरा जायेगो, साथ ही आईपीएचएस मानकों के अनुरूप नये पदों को भी सृजित किया जायेगा। साथ ही विभाग में शत-प्रतिशत पदोन्नति का लाभ भी कार्मिकों को दिया जायेगा। इसके लिये विभगाय अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं। डॉ. रावत ने कहा कि सरकार प्रदेश में मजबूत हेल्थ नेटवर्क स्थापित करने में जुटी है, खास कर पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को

(शेष पृष्ठ सात पर....)

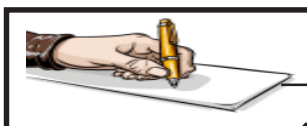

वक्फ संशोधन कानून पर फिर से सियासत

वक्फ संशोधन कानून पर फिर सियासत सुलगने लगी है। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्तूबर में हो सकते हैं, लिहाजा सियासत ध्रुवीकरण में तबदील होने लगी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए हुंकार भरी कि यदि 'इंडिया' गठबंधन चुनाव में जीता, तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने का काम करेगा। यह बिहार की 17.7 फीसदी मुस्लिम आबादी को अपने पक्ष में लामबंद करने की सियासत है। जनसभा का आयोजन 'इमारत-ए-शरिया' नामक कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन ने किया था, लिहाजा 'शरिया कानून' लागू करने की भी हुंकारें भरी गईं। भारत में सभी राज्य, यहां तक कि पंचायतें भी, संविधान से संचालित होते हैं। ये तमाम हुंकारें महज चुनावी हैं, क्योंकि ये असंवैधानिक हैं। यह देश भी इस्लामी नहीं है। फिर भी ये हुंकारें संसद के लिए गंभीर चुनौती हैं, संसद को धमका रही हैं कि उसके दोनों सदनों में पारित विधेयक और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद बने कानून को कूड़ेदान में फेंकने का आह्वान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 में स्पष्ट प्रावधान हैं कि राज्य केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को खारिज नहीं कर सकते। कृषि कानूनों का संदर्भ भिन्न है। वहां प्रधानमंत्री के आग्रह पर संसद ने अध्यादेशी कानूनों को निरस्त करने के प्रस्ताव पारित किए थे। कैबिनेट ने यह करने का आग्रह किया था। विपक्ष उन कानूनों का जो उल्लेख कर रहा है, वह गलत और सियासी है। बहरहाल वक्फ जैसे कानून को राज्य सरकारें लागू करें अथवा न करें, उसके भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, लेकिन राज्य के पास केंद्रीय कानून को नकारने की संवैधानिक शक्तियां नहीं हैं। दिलचस्प है कि 'नमाजवाद' की सियासत करने वाले अनुच्छेद 14,15, 25, 26, 29 की भी दुहाई दे रहे हैं कि वक्फ संशोधन कानून बना कर उनके मौलिक और मजहबी अधिकारों का हनन किया गया है। लेकिन वक्फ महज मजहबी मामला नहीं है। यह अकूत संपत्तियों के जरिए व्यापक भ्रष्टाचार और कब्जेबाजी का मामला है। यह विधेयक पारित करने से पहले संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) बनाई गई थी, जिसमें विपक्ष ने बराबर के विमर्श में शिरकत की थी। बहरहाल भारत के वक्फ बोर्डों के पास करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जो सेना और रेलवे के बाद सर्वाधिक है। करीब 8.72 लाख संपत्तियां वक्फ के अधीन हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल में 40,951 मुकदमे विचाराधीन हैं, जिनमें कई मामले मुसलमानों की ही शिकायत के आधार पर दर्ज किए गए हैं। बेहद अहम सवाल है कि इतने अमीर वक्फ बोर्डों के बावजूद औसत मुसलमान गरीब, अनपढ़, साधनहीन क्यों है? वक्फ कानून में पहली बार संशोधन नहीं किए गए हैं। मौजूदा सरकार वक्फ की संपत्तियों का डिजिटलीकरण कर उन्हें पारदर्शी बनाना चाहती है। प्रशासनिक स्तर पर कलेक्टर की भूमिका भी तय करना चाहती है। राजस्व रिकॉर्ड को सिलसिलेवार बनाना चाहती है। सबसे अहम संशोधन यह है कि वक्फ से जुड़े विवाद सिर्फ ट्रिब्यूनल तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें उच्च न्यायालय तक में चुनौती दी जा सकती है। बहरहाल अभी मामला सर्वोच्च अदालत के विचाराधीन है। कुल 5 याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। सर्वोच्च अदालत ने सिर्फ 2 प्रावधानों पर ही अंतरिम रोक लगाई है। अंतरिम निर्देश पर शीर्ष अदालत ने 30 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल 5 मई को यह मामला नई न्यायिक पीठ को सौंपना पड़ा, क्योंकि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो गए थे। अब मौजूदा प्रधान न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई पीठ का नेतृत्व कर रहे हैं।

महिला क्रूरता की घटनाएं व उनका समाधान

अगर किसी गुस्सैल पर्सनैलिटी वाली लडकी ने पिता से उसकी मां को प्रताडिघ्त होते देखा है, तो उसके दिमाग में ये और भी ज्यादा पुख्ता हो जाता है कि 'मैं खुद के साथ ये हरगिज नहीं होने दूंगी।' ऐसे में कई बार 10 फीसदी बंधन पर भी वह ऐसे बर्ताव करती हैं जैसे उन्हें बुरी तरह दबा रखा है। मनोविज्ञान के मुताबिक यह क्षण उनके लिए असहनीय हो जाते हैं और क्रूरता को जन्म देते हैं। ऐसे में क्रूरता के जन्म के लिए किसी महिला को जिम्मेवार ठहराना एकतरफा फैसला होगा। किसी भी रिश्ते में भरोसा एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसके साथ ही भरोसा जीतने में समय भी लगता है।

चर्चित समाचारों के मुताबिक देश में कुछ महिलाओं द्वारा अपने प्रेमियों के साथ साजिश करके कई पतियों की जीवनलीला खत्म करने की घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री इस तरह कि घटनाओं को लेकर चिंतित हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि आजकल न केवल कुछ पुरुष, बल्कि कुछ महिलाएं भी क्रूर व्यवहार का रास्ता अपनाती जा रही हैं। क्रूरता शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकती है। जीवनसाथी को शारीरिक चोट पहुंचाना जैसे शरीर, अंग या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना या मृत्यु शारीरिक क्रूरता मानी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को एक या दो कामों से गंभीर चोट पहुंचती है तो उसे शारीरिक क्रूरता माना जाएगा। किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना, नाम पुकारना, व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बदनाम करना, झूठे आरोप लगाना, जीवनसाथी के साथ वैवाहिक संबंध बनाने से इनकार करना, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक भलाई को खतरे में डालना मानसिक क्रूरता मानी जाएगी। किसी व्यक्ति के खिलाफ शारीरिक क्रूरता साबित करना अपेक्षाकृत आसान है, मानसिक क्रूरता साबित करना मुश्किल है और यह व्यक्ति की संवेदनशीलता और सामाजिक स्थिति के आधार पर अलग-अलग होता है।

क्रूरता, उत्पीडन, यातना और पीड़ा की अवधारणा हमारे समाज में लंबे समय से प्रचलित है। मनोविज्ञान के अनुसार हालात इत्यादि के चलते कुछ महिलाओं की सोच में प्यार की जगह नफरत, भरोसे ही जगह धोखा और साथ निभाने के बजाय रिश्तों को खत्म कर देने की सोच ने जन्म ले लिया है। बल्कि पिछले कुछ समय में ऐसे कई केस सामने आए हैं, जहां महिलाएं रिश्तों से उबरने की बजाय उन्हें खत्म करने का रास्ता चुन रही हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, प्रेशर या अंदर दबी भावनाएं, नई-नई शादियों में जब ऐसा होता है तो इसके पीछे का कारण या तो ये होता है कहीं शादी जबरदस्ती कराई गई है या फिर उसका पति उसे पसंद नहीं है। ऐसे में महिलाओं के मन में बैठ जाता है कि उनकी पसंद और नापसंद को जरूरी नहीं समझा जा रहा है। ऐसे में वे क्रूर होने का रास्ता चुन लेती हैं। जब कोई महिला अपने पति की हत्या करवा देती है, तो क्या ये सिर्फ क्राइम है या कोई मानसिक बीमारी? मनोवैज्ञानिक मत है कि इसे सिर्फ क्राइम नहीं कहा जा सकता है। इसे दिमागी रूप से बीमार होना भी कह सकते हैं। ऐसे में महिलाएं अपनी भावनाओं और गुस्से को बैलेंस नहीं कर पाती हैं। और गुस्से में तो इनसान हमेशा गलत कदम ही उठाता है। इसके पीछे भी यही कारण है। हम एक और बात पर ध्यान दें। हालिया घटनाओं में अधिकतर मध्यम वर्ग की ऐसी महिलाएं हैं, जो छोटे शहरों से हैं। ये देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे समाज के ढांचे में मध्यम वर्ग की महिलाओं पर ही सारे नियम लादे गए थे। वही सालों से दबी रही हैं। छोटे शहरों की ये महिलाएं सालों से बंधनों में बंधी रही हैं। अब सोशल मीडिया का एक्सेस हर किसी के पास है, इसमें सामाजिक स्तर का या छोटे शहरों का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन इन महिलाओं ने अपनी माओं को, दादियों को मर्द प्रभावी समाज से शोषित होते हुए देखा है। ऐसे में ये वो पहली जनरेशन है जो इस सामाजिक दबाव से, बंधन से बाहर निकली है। तो ऐसे में अगर किसी गुस्सैल पर्सनैलिटी वाली लडकी ने पिता से उसकी मां को प्रताडिघ्त होते देखा है, तो उसके दिमाग में ये और भी ज्यादा पुख्ता हो जाता है कि 'मैं खुद के साथ ये हरगिज नहीं होने दूंगी।' ऐसे में कई बार 10 फीसदी बंधन पर भी वह ऐसे बर्ताव करती हैं जैसे उन्हें बुरी तरह दबा रखा है। मनोविज्ञान के मुताबिक यह क्षण उनके लिए असहनीय हो जाते हैं और क्रूरता को जन्म देते हैं।

ऐसे में क्रूरता के जन्म के लिए किसी महिला को जिम्मेवार ठहराना एकतरफा फैसला होगा। किसी भी रिश्ते में भरोसा एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसके साथ ही भरोसा जीतने में समय भी लगता है। आज के समय में रिश्ते मूड पर डिपेंड हो गए हैं। महिला हो या फिर पुरुष, ये भावना आ चुकी है कि मेरी मर्जी नहीं चलेगी तो रिश्ता भी नहीं चलेगा। मूड के वशीभूत होकर, महिला हो या पुरुष, कोई भी हो, समझौता करने के बजाय रिश्तों को तोडना ज्यादा पसंद करते हैं। आजकल बहुत लोग सोशल मीडिया पर रील्स देखकर ही उसे अपनी लाइफ मान लेते हैं। वे अपने रिश्तों की तुलना रील से करने लगते हैं और घर से बाहर सुख तलाशना शुरू कर देते हैं। पुरुष भी इसका अपवाद नहीं है। अंत में कुछ महिलाओं में नशे की आदत भी बहुत बढ़ गई है। शराब, स्मोकिंग, ड्रग्स आदि का इस्तेमाल अब कुछ महिलाओं में भी बहुत ज्यादा पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। इस तरह की लत भी महिला क्रूरता की वजह बनती है। क्या ऐसे व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। महिलाओं के ऊपर क्रूरता को लेकर कुछ पुरुष भी कम नहीं होते। हर रोज महिलाओं को थप्पड़ों, लातों, पिटाई, अपमान, धमकियों, यौन शोषण और अनेक अन्य हिंसात्मक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इन सबके बावजूद हमें इस प्रकार की हिंसा के बारे में अधिक पता नहीं चलता है, क्योंकि शोषित व प्रताडिघ्त महिलाएं इसके बारे में चर्चा करने से घबराती, डरती व झिझकती हैं। महिला को चोट पहुंचाने के लिए पुरुष अनके बहाने दे सकता है, जैसे कि वह शराब के नशे में था।

शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमता : एक क्रांतिकारी अवसर

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का शिक्षा में एकीकरण केवल एक तकनीकी उन्नयन नहीं है। यह ज्ञान के वितरण, पहुंच और अनुभव के तरीके को मौलिक रूप से पुनर्परिभाषित करता है। भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए, जो बड़ी छात्र संख्या, भाषाई विविधता और संसाधनों की कमी जैसी अनूठी चुनौतियों का सामना करते हैं, एआई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने और व्यवस्थित सुधारों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। विकसित होता शैक्षिक परिदृश्य : भारतीय उच्च शिक्षा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। पारंपरिक शिक्षण पद्धतियां, हालांकि मौलिक हैं, अक्सर तेजी से बदलती दुनिया और विविध छात्र समुदाय की मांगों को पूरा करने में संघर्ष करती हैं। एआई अनुकूलनीय, मापनीय और डेटा-संचालित समाधानों के माध्यम से इन अंतरालों को पाटने की क्षमता रखता है। यह परिवर्तन शिक्षा में मानवीय तत्व को प्रतिस्थापित करने के बजाय उसे बढ़ाने के बारे में है- सीखने को अधिक उत्तरदायी, समावेशी और प्रभावी बनाने के बारे में।

व्यक्तिगत शिक्षण का विस्तार : एआई का सबसे महत्वपूर्ण योगदान पहले से असंभव माने जाने वाले पैमाने पर शिक्षण को व्यक्तिगत बनाने की क्षमता है। भारत में, जहां एक व्याख्याता को सैकड़ों छात्रों को संबोधित करना पड़ता है, व्यक्तिगत ध्यान अक्सर सीमित होता है। एआई संचालित अनुकूली शिक्षण प्लेटफॉर्म प्रत्येक छात्र के प्रदर्शन, सीखने की शैली और गति का विश्लेषण कर सकते हैं, सामग्री और मूल्यांकन को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप गतिशील रूप से समायोजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एआई जैसे प्लेटफॉर्म छात्रों की प्रगति और रुचियों के अनुरूप पाठ्यक्रमों और संसाधनों का सुझाव देने के लिए अनुशंसा एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं।

विविध शिक्षार्थियों तक पहुंच : भारत की शैक्षिक विविधता- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, कई भाषाओं और डिजिटल पहुंच के विभिन्न स्तरों को कवर करती है, लचीले समाधानों की मांग करती है। एआई बहुभाषी वर्चुअल सहायकों, विभिन्न पृष्ठभूमियों के लिए अनुकूलित इंटरैक्टिव सामग्री और विकलांग छात्रों के लिए पहुंच सुविधाएं प्रदान करके इन विभाजनों को पाटने में मदद कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि भौगोलिक स्थिति या भाषा की परवाह किए बिना सभी के लिए सुलभ हो।

शिक्षकों को सशक्त बनाना, प्रतिस्थापित नहीं करना : एआई दोहराव वाले और प्रशासनिक कार्यों को स्वचालित करने में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, जैसे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनों को ग्रेड करना, उपस्थिति की निगरानी करना और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना। यह स्वचालन शिक्षकों को मूल्यवान समय वापस देता है, जिसे मेंटरशिप, चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देने जैसे अधिक प्रभावशाली गतिविधियों की ओर पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। शिक्षा का वास्तविक मूल्य शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंधों में निहित है। एआई छात्रों के प्रदर्शन में अंतर्दृष्टि प्रदान करके, शीघ्र हस्तक्षेप को सक्षम करके और अधिक सार्थक जुड़ाव की अनुमति देकर इन संबंधों का समर्थन कर सकता है। उदाहरण के लिए, अमृता विश्वविद्यालय का एआई चौटबॉट रूटीन इंजीनियरिंग प्रश्नों को संभालता है, जिससे प्रोफेसर जटिल, वैचारिक शिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

डेटा-संचालित छात्र सहायता प्रणालियां : एआई की विशाल मात्रा में डेटा को संसाधित करने की क्षमता विश्वविद्यालयों को पैटर्न की पहचान करने और परिणामों की भविष्यवाणी करने में सक्षम बनाती है। उपस्थिति, एसाइनमेंट सबमिशन और मूल्यांकन डेटा का विश्लेषण करके एआई मॉडल उन छात्रों को चिह्नित कर सकते हैं जो पिछडने या ड्रॉपआउट होने के जोखिम में हो सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के पायलट कार्यक्रम, जिसने भविष्य कहने वाला विश्लेषण का उपयोग किया, ने ड्रॉपआउट दरों में 15 फीसदी की कमी हासिल की, समय पर, डेटा-संचालित हस्तक्षेपों की शक्ति का एक प्रमाण। इन अंतर्दृष्टियों के साथ, विश्वविद्यालय प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप ट्यूटरिंग, काउंसिलिंग या अतिरिक्त संसाधनों जैसे लक्षित सहायता कार्यक्रमों को डिजाइन कर सकते हैं। यह सक्रिय दृष्टिकोण न केवल प्रतिधारण दरों में सुधार करता है, बल्कि समग्र छात्र अनुभव और सफलता को भी बढ़ाता है।

आपातकाल में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को जोड़ा, इसकी समीक्षा हो

-आरएसएस के महासचिव ने कहा-मूल संविधान में इनका कोई स्थान नहीं था

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बार फिर संविधान की प्रस्तावना में शामिल 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में इन शब्दों की समीक्षा करने की जरुरत जताई। उनका कहना है कि ये शब्द आपातकाल में असंवैधानिक तरीके से जोड़े गए थे और बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा तैयार मूल संविधान में इनका कोई स्थान नहीं था।

होसबोले ने कहा कि आपातकाल के समय जब मौलिक अधिकार निलंबित थे, संसद निष्क्रिय थी, न्यायपालिका दबाव में थी, तब कांग्रेस सरकार ने चुपचाप प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' जैसे शब्द जोड़ दिए थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये विचारधाराएं भारत के लिए शाश्वत हैं? इस पर विचार और बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज वही लोग संविधान की प्रति लेकर घूम रहे हैं, जिन्होंने 1975 में संविधान की आत्मा को रौंदा था। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लगाए गए आपातकाल के दौरान हजारों लोगों को जेल में डाला गया, मीडिया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता छीन ली गई और बड़ी संख्या में जबरन नसबंदी की गई।

होसबाले ने कांग्रेस से देश से माफी मांगने की मांग करते हुए कहा कि आपके पूर्वजों ने जो किया, उसके लिए आज आपको माफी मांगना जरूरी है। आज लोकतंत्र की दुहाई देने वाले आपातकाल के काले अध्याय को भूल नहीं सकते। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी आपातकाल की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर सबसे बड़ा हमला था। संविधान में बदलाव कर जनता की आवाज को कुचल दिया गया। कांग्रेस आज आरोप लगा रही है कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, जबकि हमने कभी ऐसी मंशा नहीं जताई।

उन्होंने कहा कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए इमरजेंसी के दौरान समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। आरएसएस का तर्क है कि यह राजनीतिक उद्देश्य से लिया गया कदम था, जिसे आज फिर समीक्षा की दृष्टि से देखा जाना चाहिए।

मीम्स और रील्स को लेकर मौलाना गोरा ने मुसलमान युवक-युवतियों को क्या दी सलाह

नई दिल्ली। इस्लामी विद्वान और जमीयत दावातुल मुस्लिमीन के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा ने मुसलमानों को सोशल मीडिया पर दीन और इस्लामी पहचान का मजाक उड़ाने से सख्ती से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मजाक में भी अगर कोई इस्लामी तालीमात, कुरान, हदीस, नमाज, हिजाब या दाढ़ी जैसी चीजों का अपमान करता है, वह इस्लाम से बाहर हो सकता है। मौलाना गोरा ने आज सोशल मीडिया पर मीम्स और रील्स के द्वारा इस्लाम और उसकी पवित्र चीजों को हंसी का साधन बनाया है। उन्होंने कहा, नमाज, अजान, रोजा, हिजाब, उलमा और यहां तक निकाह और तलाक जैसे शरियत के गंभीर मसलों पर कॉमेडी वीडियो बन रहे है।

गोरा ने अफसोस जताया कि कई मुस्लिम युवक युवतियां बिना सोचे समझे इसतरह के वीडियो को लाइक शेयर या कमेंट करके उसका प्रचार करते हैं। मौलाना ने कहा कि शरीयत के अनुसार इस तरह की मजाकिया बातों को देखना हंसना या दूसरों को दिखाना भी बड़ा गुनाह है। गोरा ने अपील कर कहा अगर कोई नादानी में ऐसा कुछ कर भी चुका है, तब फौरन तौबा करे। इस्लाम मजाक का विषय नहीं है बल्कि यह एक बड़ी अमानत है। इससे पहले भी कई इस्लामी विद्वान सोशल मीडिया पर इसतरह के ट्रेंड्स पर चिंता जता चुके हैं। दारुल उलूम देवबंद सहित कई प्रमुख संस्थानों ने इस बारे में फतवे भी जारी किए हैं। अब मौलाना गोरा का बयान मुद्दे पर चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है।

लालू-नीतीश ने अपने शासनकाल में पूरे बिहार को मजदूरों का राज्य बनाया : प्रशांत किशोर

पटना (एजेंसी)। जन सुराज पार्टी के संस्थापक और पूर्व रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल (यूनाइटेड) पर निशाना साधकर कहा कि इनके शासन में बिहार मजदूरों का राज्य बना है। किशोर ने कहा कि बिहार में गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी को खत्म करने का एकमात्र उपाय शिक्षा है। लालू-नीतीश के बीते 30-35 सालों के शासन ने पूरे बिहार को मजदूरों का राज्य बनाया है। यहां के बच्चे अपनी पीठ पर बोरा ढोने को मजबूर हैं। जन सुराज की विचारधारा यह है कि बिहार के बच्चे अपनी पीठ पर बोरा नहीं, बल्कि स्कूल बैग उठाएंगे, अच्छी जिंदगी जीएं।

चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जन सुराज को आम चुनाव चिन्ह के रूप में स्कूल बैग आवंटित किया है। फैसले का स्वागत कर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि राज्य में गरीबी, निरक्षरता और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। इससे पहले, एक साक्षात्कार में पीके ने कहा कि केंद्र में पीएम मोदी के 11 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद बिहार गरीबी, भुखमरी और लाचारी से जूझ रहा है।

उन्होंने सवाल किया, हम अभी भी भूख, गरीबी और लाचारी का सामना कर रहे हैं। हम इस सरकार से पूछते हैं, राज्य में बीस साल और केंद्र में ग्यारह साल सत्ता में रहने के बाद, आप एक भी ऐसा क्षेत्र बताइए जहां बिहार राष्ट्रीय स्तर पर नंबर एक पर है?

वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने जताई चिंता

कहा- छोटी पार्टियों को होगा नुकसान, बड़ी पार्टियों के पास होता है पैसा

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने वन नेशन, वन इलेक्शन कराने की योजना पर चिंताएं जताई हैं। उन्होंने इसपर विचार के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कहा कि छोटी और राष्ट्रीय पार्टियों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। उनका मानना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो छोटी पार्टियां पिछड़ जाएंगी। जेपीसी इस मामले पर विचार कर रही है और 11 जुलाई को पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेएस खेहर से बात करेगी।

केंद्र सरकार 2029 से एक साथ यानी वन नेशन, वन इलेक्शन कराने पर विचार कर रही है, ताकि चुनाव का खर्च कम हो और सरकारें विकास पर ध्यान दे सकें। मौजूदा परिस्थितियों में यह 2034 से ही पूरी तरह से लागू होने की संभावना है। कई पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि इससे लोकतंत्र और संघीय ढांचे को नुकसान होगा।

मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने जेपीसी को बताया कि एक साथ चुनाव कराने से छोटी पार्टियों को नुकसान होगा। क्योंकि बड़ी पार्टियों के पास ज्यादा पैसा होता है, जिससे वे चुनाव में आगे रहती हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के नियमों को मजबूत करना चाहिए, खासकर पैसे के मामले में। अभी उम्मीदवारों के खर्च की सीमा है, लेकिन पार्टियों के खर्च की कोई सीमा नहीं है। इससे बड़ी पार्टियों को फायदा होता है।

उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा या विधानसभा कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो जाती है, तो दोबारा चुनाव होने चाहिए। इससे लोगों को हमेशा अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रस्ताव संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तभी करेगा, जब सरकार के हर स्तर पर गैर-समकालिक चुनाव संविधान का मूल तत्व हो। चंद्रचूड़ ने अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि संसदीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हमेशा सदन का समर्थन मिलना चाहिए। अगर अविश्वास प्रस्ताव लाने पर समय की पाबंदी होगी, तो यह सिद्धांत कमजोर हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि भारत जैसे बहुदलीय लोकतंत्र में किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिलना मुश्किल होता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव पर निर्भर है, तो अल्पसंख्यक सरकार के सत्ता में बने रहने की संभावना है। यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। जेपीसी अभी विधेयक की जांच कर रही है। इस बिल में अनुच्छेद 82(ए) जोड़ने का प्रस्ताव है, जो लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव से जुड़ा है। इसके अलावा अनुच्छेद 83, 172 और 327 में भी बदलाव करने की बात है। ये बदलाव 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद लागू होंगे और एक साथ चुनाव 2034 से शुरू हो सकते हैं।

बता दें आजादी के बाद 1952 से 1967 तक देश में एक साथ चुनाव हुए थे, लेकिन बाद में लोकसभा और विधानसभाएं समय से पहले भंग होने लगीं, जिससे चुनाव अलग-अलग समय पर होने लगे। कई समितियों ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया है, लेकिन कुछ दिक्कतें भी बताई हैं।

ममता को डर... बांग्लादेशी घुसपैठियों वाला उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा

बीजेपी नेताओं ने निर्वाचन आयोग के नए फैसले का स्वागत किया

कोलकाता (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के नए मतदाता सूची संशोधन नियमों पर नकारात्मक टिप्पणियां उनके हार के डर को दिखा रही हैं। उन्हें डर है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का उनका समर्पित वोट बैंक खतरे में आ सकता है। ममता ने कहा कि ईसीआई के नए दिशानिर्देश इस साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जारी हुए हैं, लेकिन वास्तव में ये नियम मुख्य रूप से बंगाल को निशाना बनाते हैं, जहां अगले साल चुनाव होने हैं। उन्होंने आशंका जाहिर कि है कि ये नए नियम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने की दिशा में एक कदम हो सकते हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता को यह डर सता रहा है कि लंबे समय से सत्ता का खुश भोगने में मददगार रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए, जिसमें रोहिंग्या पृष्ठभूमि वाले लोग भी शामिल हैं, उन्हें अब हटाया जाएगा और इसलिए वे आयोग पर हमलावार हैं।

उन्होंने कहा, हम ईसीआई के दिशानिर्देशों का स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ा दिया जाए। हम बायोमैट्रिक चाहते हैं। ममता को डर है, क्योंकि उनके समर्पित वोट बैंक के कई लोग अब हटाए जाएंगे।

हाल ही में दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप उप-मंडल के न्यूटन दास नाम के व्यक्ति को आयोग ने भारत और बांग्लादेश दोनों की मतदाता सूचियों में शामिल पाया। इसके बाद उनका नाम भारत की मतदाता सूची से हटाया गया। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी ममता के ईसीआई के नियमों पर डर को लेकर उनकी टिप्पणियों पर तंज कसा।

उनके अनुसार, मुख्यमंत्री का यह आरोप कि ईसीआई के दिशानिर्देश एनआरसी लागू करने का पहला कदम है, यह हैरान करने वाला और गैर-जिम्मेदाराना है, क्योंकि आयोग की ऐसी प्रक्रियाएं वैधानिक और नियमित हैं, जिनका उद्देश्य बंगाल की मतदाता सूचियों में शामिल किया जाना था।

उद्धव और राज ठाकरे एक साथ मिलकर करेंगे हिंदी का विरोध

- सोशल मीडिया पर ठाकरें ब्रदर्स ने लिखा, महाराष्ट्र की जय हो

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य किए जाने के मामले ने उद्धव और राज ठाकरे को एक बार फिर साथ आने का मौका प्रदान किया है। इस मुद्दे को लेकर उद्धव और राज ठाकरे एक साथ मिलकर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसकी जानकारी स्वयं शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने दी है। शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक फोटो शेयर किया। इसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र के स्कूलों में अनिवार्य हिंदी के खिलाफ एकजुट प्रदर्शन होगा। ठाकरे ही ब्रांड हैं। इसके अलावा राउत ने एक अन्य पोस्ट भी शेयर की और इस तस्वीर में उद्धव और राज ठाकरे एक साथ खड़े हुए दिख रहे हैं, जबकि उनके पीछे बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर दिख रही है। उन्होंने इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, महाराष्ट्र की जय हो।हिंदी भाषा पर महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया गया है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज ठाकरे ने मुंबई में 6 जुलाई को मार्च का आह्वान किया था और उद्धव ठाकरे ने 7 जुलाई को मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन की घोषणा की थी, लेकिन अब संजय राउत ने बताया है कि वे दोनों एक साथ आंदोलन करेंगे। इससे पहले, शिवसेना (उद्धव गुट) प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र सरकार पर हिंदी भाषा को जबरदस्ती थोपने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने एक बयान में कहा था, वर्तमान सरकार राज्य पर हिंदी लादने की कोशिश कर रही है। उनका किसी भाषा या हिंदी भाषी समुदाय से कोई विरोध नहीं है, बल्कि वह जबरन किसी भाषा को थोपने के खिलाफ हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी की बांटने और काटने की नीति स्पष्ट है। वह मराठी और अन्य भाषियों के बीच जो एकता है, उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है।

इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 की घोषणा की, आर्चर टीम में नहीं

लंदन (एजेंसी)। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए सोमवार 30 जून को अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा की, जो बुधवार से बर्मिंघम के एजबेस्टन में शुरू होगा। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने जीत दर्ज करते हुए पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में बढ़त बनाई थी।

बेन स्टोक्स की अगुआई वाली टीम में दूसरे मैच के लिए टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उंगली की चोट से उबरने के बाद इंग्लैंड की टीम में शामिल किए गए तेज गेंदबाज जोफा आर्चर को शुरुआती लाइनअप में शामिल नहीं किया गया है। आर्चर परिवार में इमरजेंसी के कारण एजबेस्टन में सोमवार के अभ्यास सत्र का हिस्सा नहीं बन पाए। वहीं जोश टंग, ब्रायडन कार्स और क्रिस वोक्स फंटलाइन तेज गेंदबाज के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे।

दूसरी तरफ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दूसरे मैच के लिए आराम दिए जाने की उम्मीद है जिससे भारत की लाइनअप में बदलाव देखने को मिल सकता है। बुमराह के अलावा भारतीय टीम में स्पिनर कुदलीप यादव को भी शामिल करने की बात सामने आ रही है जो लंदन में प्रभावी साबित हो सकते हैं।

इंग्लैंड की प्लेइंग 11

जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), क्रिस वोक्स, ब्रायडन कार्स, जोश टंग, शोएब बशीर।

ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज ग्रेग चैपल ने भारत की सबसे बड़ी कमी पर जताई चिंता

लंदन (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज ग्रेग चैपल का मानना है कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत को गेंदबाजी आक्रमण में विविधता के अभाव का खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने कुलदीप यादव को शेन वॉर्न के बाद सर्वश्रेष्ठ कलाई का स्पिनर करार देते हुए उन्हें और अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल करने की सलाह दी। भारत को पांच मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में इंग्लैंड ने पांच विकेट से हराया।

भारतीय टीम ने पहले टेस्ट में आठ कैच टपकाए। चैपल ने अपने कॉलम में लिखा, 'हेडिंग्ले में फील्डिंग बहुत निराशाजनक थी लेकिन हार का यह अहम कारण नहीं था। भारत ने अपनी परेशानियां खुद खड़ी की थी। सबसे बड़ी गलती तो वह नो बॉल थी जिससे दूसरी पारी की शुरूआत में ही हैरी ब्रूक को जीवनदान मिला।'

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने कहा कि भारत के सामने समस्या यह भी थी कि उसके दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर लगभग एक से ही थे। उन्होंने कहा, 'भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में विविधता का अभाव था। जसप्रीत बुमराह को छोड़कर बाकी तेज गेंदबाज एक जैसे ही थे। गेंदबाजी में बदलाव के तुरंत बाद विकेट गिरने का कारण यह होता है कि बल्लेबाज को ढलने में समय लगता है। लेकिन भारतीय टीम के पास यह विकल्प नहीं था।'

भारत के पूर्व कोच ने कहा, 'बुमराह की गैर मौजूदगी में अर्शदीप सिंह को टीम में जगह मिलनी चाहिए। इसके साथ ही कुलदीप यादव को भी उतारना चाहिए जो शेन वॉर्न के बाद कलाई का सर्वश्रेष्ठ स्पिनर है।'

भारतीय टीम ने टी20 विश्वकप जीत के एक साल पूरा होने पर केक काटकर जश्न मनाया

लंदन (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप 2024 की जीत के एक साल पूरे होने पर रविवार को यहां एक पार्टी आयोजित की। इसमें केक काटकर जश्न मनाया गया। इस दौरान विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने मजाकिया अंदाज में ऑलराउडर रवींद्र जडेजा की खिंचाई करने का प्रयास किया पर उन्हें करारा जवाब मिला। जडेजा ने कहा कि वह अभी एक फॉर्मेट से रिटायर हुए हैं। टी20 विश्व कप जीतने के बाद जडेजा ने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारुप से संन्यास ले लिया था।

बीसीसीआई ने इस पार्टी का वीडियो भी सोशल मीडिया में पारी किया है। वीडियो में देखने को मिल रहा है कि पहले कोई भी खिलाड़ी केक काटने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी अर्शदीप सिंह आगे बढ़े तो कहा गया कि बुमराह प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, तो ऐसे में अर्शदीप की जगह बुमराह ने केक काटा। इसके बाद सभी खिलाड़ी एक दूसरे को केक खिलाने लगे। वीडियो में बुमराह और ऋषभ ने जडेजा को 'हैप्पी रिटायरमेंट' कहकर केक खिलाया। इसपर जडेजा सफाई देते नजर आ रहे हैं उन्होंने अभी केवल एक ही प्रारुप से संन्यास लिया है।

शमी होते तो बुमराह को मिलता एक अनुभवी जोड़ीदार !

बर्मिंघम । भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को कार्यभार प्रबंधन के तहत ही दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में आराम दिया जाएगा। ऐसे में टीम को अनुभवी तेज गेंदबाज मोशमी की याद आई है। शमी को इस सीरीज के लिए इसलिए जगह नहीं मिली क्योंकि वह पूरी तरह से फिट नहीं थी। इससे पहले आईपीएल में उनका प्रदर्शन भी उम्मीद के अनुसार नहीं रहा था। ऐसे में उन्हें टीम में शामिल न करने के लिए प्रबंधन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि आईपीएल 2025 में वह नौ मैचों में 56 की औसत से केवल छह विकेट ले पाये थे। वहीं इसके बाद भी शमी को खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने 5 मैचों में 25 की औसत से 9 विकेट लिए। इंग्लैंड दौरे पर 34 वर्षीय तेज गेंदबाज शमी को ना चुने जाने से उनके टेस्ट करियर के समाप्त होने की भी आशंका लगायी गयी पर ये सही नहीं है। अभी भी शमी बुमराह के लिए एक अच्छे सहयोगी हैं। आज जबकि बुमराह केवल तीन टेस्ट खेल कसते हैं तो सभी को शमी की याद आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि शमी को कम से कम दो टेस्ट के लिए तो शामिल किया जा सकता था। वह भी उनक मैचों में जिनमें बुमराह नहीं होते। शमी ने इंग्लैंड में 14 मैचों में 42 विकेट लिए हैं और वह टीम की ओर से अहम भूमिका निभा सकते थे। शमी के नहीं होने से टीम इंडिया अभी तक बुमराह के लिए सही जोड़ीदार तलाशने में असफल रही है। युवा मोहम्मद सिराज फॉर्म में नहीं हैं। वहीं आकाश दीप और प्रसिद्ध कृष्णा भी अनुभवी नहीं हैं।

एशिया कप भारत में, पाकिस्तान को नहीं मिलेगी देश में एंट्री !, हॉकी इंडिया के अधिकारी का बयान आया सामने

नई दिल्ली (एजेंसी)। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में हॉकी पुरुष एशिया कप में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर अनिश्चितता के बीच हॉकी इंडिया के एक अधिकारी ने कहा कि इस मामले में सरकार के साथ बातचीत जारी है और उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। बिहार का ऐतिहासिक शहर राजगीर 29 अगस्त से 9 सितंबर तक राजगीर हॉकी स्टेडियम में पुरुष एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा।

पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले में 26 लोगों की जान जाने के बाद पाकिस्तान पुरुष हॉकी टीम की महाद्वीपीय प्रतियोगिता में भागीदारी खतरे में है। टूर्नामेंट में दो महीने से भी कम समय बचा है और हॉकी इंडिया अभी भी पाकिस्तान पुरुष हॉकी टीम के देश में आने के लिए सरकारी मंजूरी का इंतजार कर रहा है। हॉकी इंडिया के एक अधिकारी ने अगस्त में एशिया कप में पाकिस्तान की भागीदारी के बारे में पूछे जाने पर कहा, 'हम सरकार के संपर्क में हैं और हम उसके निर्देशों का पालन करेंगे। मौजूदा स्थिति के अनुसार मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम को भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।'

पुरुषों का एशिया कप 2025-2026 एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए क्वालीफाइंग इवेंट के रूप में काम करेगा, जिसकी मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड करेंगे। टूर्नामेंट का विजेता विश्व कप में एक प्रतिष्ठित स्थान अर्जित करेगा। इसके अलावा भारत एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की भी मेजबानी करेगा, जो 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरै में खेला जाएगा।

पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को बाहर करने की मांग के कारण भारत में जूनियर इवेंट में पाकिस्तान की भागीदारी भी संदेह में है। उन्हें विस्तारित 24-टीम टूर्नामेंट में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के साथ रखा गया था। पाकिस्तान की पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार 2023 में भारत का दौरा किया था, जब भारत ने चेन्नई, तमिलनाडु में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की थी। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने फाइनल में मलेशिया को 4-3 से हराकर रिकॉर्ड चौथा खिताब जीता था।

अजहर महमूद पाकिस्तान टेस्ट टीम के नए मुख्य कोच बने

लाहौर । पूर्व ऑलराउंडर अजहर महमूद पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बनाये गये हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अजहर के नाम की घोषणा कर दी है पर कहा है कि वह वह शुरुआत में कार्यवाहक मुख्य कोच रहेंगे। अजहर पिछले काफी समय से पुरुष क्रिकेट टीम के गेंदबाजी और असिस्टेंट कोच रहे हैं। वह अपने मौजूदा अनुबंध के समाप्त होने तक इस पद पर काम करेंगे। पिछले दो साल में पीसीबी ने कई मुख्य कोच बदले हैं, ऐसे में महमूद कब तक टिक पायेंगे ये देखना होगा। पीसीबी को भरोसा है कि अजहर कोच को खिलाड़ी और कोच के रूप में काफी अनुभव है, इसलिए वह इस भूमिका में सफल रहेंगे। पीसीबी ने कहा, एक अनुभवी क्रिकेट खिलाड़ी अजहर अब कोच के तौर पर आ रहे हैं। टीम के सहायक कोच के रूप में लंबे समय से रहने के कारण वह टीम के रणनीतिक कोर समूह का एक अहम हिस्सा रहे हैं। खेल के बारे में उनकी जानकारी काफी अच्छी है। अंतरराष्ट्रीय अनुभव के साथ हीइंग्लिश काउंटी सर्किट में मिली सफलता उन्हें इस पद के लिए सबसे अधिक उपयुक्त बनाती है। महमूद की कोच के तौर पर पहली परीक्षा आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत दक्षिण अफ्रीका की धरती पर होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ शुरू होगी। ये सीरीज इस साल के अंत में खेली जाएगी।

भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलने से नाराज हैं पूर्व क्रिकेटर फारुख इंजीनियर

बर्मिंघम (एजेंसी)। पूर्व क्रिकेटर फारुख इंजीनियर ने भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का नाम बदले जाने पर नाराजगी जताया है। इस पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि ये फैसला प्रशंसकों को खुश करने के लिए किया गया। ईसीबी ने साल 2007 में भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम पटौदी ट्रॉफी रखा था पर इस बार इसका नाम बदलकर एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया। इस फैसले को दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी सही नहीं माना था। इंजीनियर भी नाम बदलने से सहमत नहीं हैं हालांकि उन्होंने माना है कि सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन की उपलब्धियों पर सवाल नहीं उठाये जा सकते हैं। इंजीनियर ने कहा, 'टाइगर पटौदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे बहुत अच्छे सहयोगी थे। हमने काफी टेस्ट मैच साथ में खेले। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब 2007 में ट्रॉफी का नाम उनके नाम पर रखा गया।

उन्होंने कहा, 'एक ओर जहां मैं इस बात से बहुत निराश हूं कि पटौदी का नाम हटा दिया गया। मैं चाहता हूं कि टाइगर का नाम इस ट्रॉफी से जुड़ा रहता लेकिन इसके बजाय सचिन और एंडरसन के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखने का फैसला किया गया जो खेल के दिग्गज हैं। इंजीनियर ने कहा, 'इसमें पटौदी पदक की शुरुआत एक अच्छा कदम है। उन्हें इसकी घोषणा शुरू में ही कर देनी चाहिए थी, इससे अधिक विश्वसनीयता होती, लेकिन कम से कम उन्होंने कुछ तो किया। उम्मीद है कि पटौदी पदक के जरिये ये नाम इससे हमेशा जुड़ा रहेगा।

पटौदी परिवार का भारत-इंग्लैंड क्रिकेट से गहरा नाता रहा है। इफ्तिखार अली खान पटौदी और उनके बेटे मंसूर दोनों ने भारत की कप्तानी की थी। इन दोनों ने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेला। वहीं दूसरी ओर तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जबकि एंडरसन ने तेज गेंदबाज के रूप में पारंपरिक प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लिए हैं। इंजीनियर ने कहा, 'तेंदुलकर और एंडरसन की उपलब्धियों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इस कहानी के दो पहलू हैं। उन्होंने पदक का नाम पटौदी के नाम पर रखा है जो बहुत सोच-समझकर किया गया फैसला है। उन्होंने कहा, 'यह फैसला पटौदी के मुझे जैसे कई समर्थकों को खुश करने के लिए किया गया लेकिन आप उन्हें ट्रॉफी का नाम सचिन और एंडरसन के नाम पर रखने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते।

विपक्ष संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की मानसिकता से नहीं आ पा रहा बाहरः सुधांशु

नई दिल्ली (एजेंसी)। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सोमवार को नई दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि वह कहते हैं कि संसद के कानून को (वक्फ बोर्ड कानून) कूड़ेदान में फेंक देंगे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अभी हाल ही में हमने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे दुर्दांत काले अध्याय आपातकाल के 50 साल पूरे किए हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के सम्मान के लिए जान की परवाह किए बिना लाखों लोग एकत्र हुए थे। वहां कल एक ऐसी रैली हुई, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि संसद के कानून को (वक्फ बोर्ड कानून) कूड़ेदान में फेंक देंगे। जबकि यह कानून दोनों सदनों से पारित है और कोर्ट में विचाराधीन है। इसका अर्थ ये हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। यह साफ है कि 50 साल बाद भी इंडी गठबंधन संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की पुरानी आदत से बाहर नहीं आ पाया है।

उन्होंने कहा कि वोट बैंक की चाहत में इंडी गठबंधन के सहयोगी तेजस्वी द्वारा जो कुछ बोला गया है, उससे साफ है कि ये संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सुधांशु ने वक्फ का जिक्र करते हुए कहा कि मैं यह बताना चाहता हूं कि कुरआन में 'वक्फ' जैसा कोई शब्द नहीं है। यह मौलवियों का बनाया शब्द है। इस्लाम आपको खर्च करना और देना सिखाता है, न कि रखना या जमा करना और फिर भी, आप कहते हैं, +संग्रह करो÷? यह बाबा साहेब के संविधान का मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ नहीं है, इसे धर्मनिरपेक्ष दस्तावेज से मौलवियों की स्क्रिप्ट में बदलने की कोशिश है। यह चंद मुस्लिमों के साथ खड़े हैं, जो पैसों की ताकत रखते हैं। यह गरीब मुस्लिमों के साथ नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि अगर वे कभी सत्ता में आए तो यह संभव नहीं है, लेकिन वे बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को कूड़ेदान में फेंक देंगे और शरिया कानून लागू करेंगे। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। याद रखें भारत में सरकार ने केवल एक बार 400 सीटें पार की हैं, वो भी 1985 में और फिर क्या हुआ? शाहबानो मामले को देखें। उस 400 से ज्यादा की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कुचल दिया और शरिया कानून को संविधान से ऊपर रख दिया। वे पिछड़े, वांछित, का आरक्षण भी यह खत्म करना चाहते हैं।

उन्होंने जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एससी/एसटी और ओबीसी आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया। सुधांशु ने कहा कि 2012 और 2014 में माइनॉरिटी संस्थाओं को दर्जा दिया गया। तेलंगाना और कर्नाटक में मुस्लिम को ओबीसी में शामिल किया गया। बंगाल में भी यही हो रहा है। तर्क यह दिया गया कि यह मुस्लिम पहले ओबीसी हिंदू समुदाय से थे और बाद में यह कन्वर्ट हुए, इसलिए इन्हें ओबीसी में डाला गया। इंडी गठबंधन के सपनों को हम साकार नहीं होने देंगे। देश का विधान बाबा साहेब के संविधान से चलेगा।

देवेंद्र फडणवीस पर हमलावर संजय राउत, झूठ बोलना भाजपा की राष्ट्रीय नीति

मुंबई । शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा तीन-भाषा नीति पर माशेलकर समिति की रिपोर्ट स्वीकार करने के झूठे दावा करने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा। सांसद राउत ने कहा कि झूठ बोलना भाजपा की राष्ट्रीय नीति है। उन्होंने भाजपा को चुनौती देकर कहा कि अगर ठाकरे ने माशेलकर समिति की रिपोर्ट पेश की थी, तब उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। ठाकरे गुट के नेता राउत ने कहा कि झूठ बोलना भाजपा की राष्ट्रीय नीति है। ये लोग महाराष्ट्र में इसी नीति के तहत काम कर रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे ने माशेलकर समिति पर कोई रिपोर्ट पेश की है, तब उस रिपोर्ट को फडणवीस सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। एक समिति की रिपोर्ट जारी की गई है और कैबिनेट में रखी गई है। क्या इस पर चर्चा नहीं हो सकती? आपने कैबिनेट के साथ जबरदस्ती हिंदी पर चर्चा की, आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह एक राष्ट्रीय नीति है। राउत ने तंज कसते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस तीन बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, क्या उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है? इसके पहले 29 जून को, विपक्ष की भारी आलोचना का सामना करने और राज्य के लोगों पर 'हिंदू भाषा थोपने' के आरोप के बाद महाराष्ट्र सरकार ने तीन-भाषा नीति के कार्यान्वयन पर दो आदेशों को रद्द किया था। महाराष्ट्र सरकार के एक प्रेस नोट के अनुसार, 24 जून को मुख्यमंत्री फड़णवीस ने तीन-भाषा फॉर्मूले पर घोषणा कर आरोप लगाया था कि यह पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे थे जिन्होंने कक्षा 1 से 12 तक तीन-भाषा नीति शुरू करने के लिए डॉ रघुनाथ माशेलकर समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था और इसके कार्यान्वयन के लिए एक पैनल भी गठित किया था।

कांग्रेस सांसद सोवियत रुस के एजेंट के तौर पर करते थे काम, मिलती थी फंडिंग

-बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

गोड्डा (एजेंसी)। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के दिवंगत नेता एचकेएल भगत के नेतृत्व में 150 से ज्यादा कांग्रेस के सांसद सोवियत रूस से फंडिंग करते थे और उसके ऐजेंट के तौर पर काम करते थे। सांसद ने ये आरोप यूएस एजेंसी सीआईए द्वारा 2011 में जारी दस्तावेज के आधार पर लगाए हैं।

दुबे ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस, भ्रष्टाचार और गुलामी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता दिवंगत एचकेएल भगत के नेतृत्व में 150 से ज्यादा कांग्रेस के सांसद सोवियत रूस के पैसे पर पलते थे और रूस के लिए दलाली करते थे। दुबे ने पत्रकारों के समूह पर एजेंट के तौर पर काम करने की बात भी पोस्ट में लिखी। पत्रकारों के समूह उनके दलाल थे और कुल 16 हज़ार न्यूज़ आर्टिकलों का जक्रि है जो रुस ने छपवाए।

नेताओं की फंडिंग और पत्रकारों की दलाली के अलावा रूसी लोगों के हिन्दुस्तान में रहने के भी आरोप लगाए हैं। दुबे ने आगे लिखा कि उस जमाने में रुस के जासूसी संस्थानों के 1100 लोग हिंदुस्तान में थे जो नौकरशाही, व्यापारी संगठनों, कम्युनिस्ट पार्टियों, ओपिनियन मेकर को अपनी जेब में रखते थे और सूचना के साथ भारत की नीति बनाते थे। दुबे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की उम्मीदवार सुभद्रा जोशी ने लोकसभा चुनाव में उस वक़्त 5 लाख रुपए लिए थे। जर्मन सरकार से चुनाव के नाम पर। हारने के बाद इंडो जर्मन फोरम की अध्यक्ष बनीं। दुबे सवालिया अंजाद में लिखा- यह देश था या गुलामों, दलालों या बिचौलियों की कठपुतली। कांग्रेस इसका जवाब दे?

सिंधु जल संधि को स्थगित करने से क्या लाभ, शिवराज, पाटिल और भूपेंद्र यादव जनता को बताएंगे

पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में व्यापक जनसंपर्क अभियान

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र की मोदी सरकार अपने वरिष्ठ मंत्रियों को जनता के बीच भेजेगी, ताकि वे लोगों को समझा सकें कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला कितना फायदेमंद है। सूत्रों के अनुसार, जनता को समझाया जाएगा कि इस संधि को क्यों स्थगित किया और इससे भारत को कैसे और कितना फायदा होगा।

खासकर उत्तर भारत के उन राज्यों में सांसदों को पहुंचाया जाएगा, जहां भविष्य में नदियों के पानी के इस्तेमाल की ज्यादा संभावना है। इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जैसे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी मिली है।

भारत सिंधु नदी के पानी का अपने लिए बेहतर इस्तेमाल करेगा और इसके लिए दीर्घकालिक रणनीति पर काम कियास जा

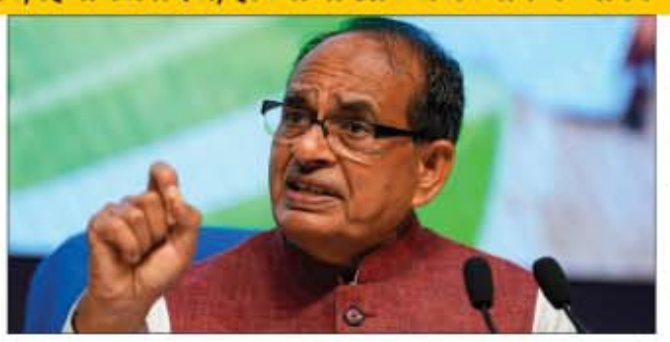

रहा है। इसमें 160 किलोमीटर नहर बनाना शामिल है, ताकि चिनाब को रावी, ब्यास और सतलुज नदी तंत्र से जोड़ा जा सके। सिंधु नदी के पानी को अन्य नदियों और नहरों से जोड़ने के लिए योजना के तहत करीब 13 किलोमीटर की टनल भी बनेगी। मोदी सरकार की योजना सिंधु जल को राजस्थान के श्रीगंगानगर से जोड़ने की है और इस तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। इससे इन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता बढ़ेगी और सिंचाई तथा बिजली उत्पादन में भी मदद मिलेगी।

सिंधु जल को श्रीगंगानगर से जोड़ने की योजना

मोदी सरकार की योजना पानी जम्मू-कश्मीर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक ले जाने की है। सरकार की योजना सिंधु जल को श्रीगंगानगर से जोड़ने की है और तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की मौजूदा 13 नहर व्यवस्थाओं को जोड़ा जाएगा।

इससे न केवल इन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता बढ़ जाएगी बल्कि भारत सरप्लस पानी का इस्तेमाल भी अपने लिए कर सकता है। साथ ही सिंचाई और बिजली उत्पादन में भी बड़ी मदद मिलेगी। मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री उन सभी इलाकों में लोगों से संपर्क करने वाले हैं, जिन्हें भविष्य में इस पानी का फायदा मिलने वाला है और बताएंगे कि मोदी सरकार के इस फैसले से उन्हें आने वाले सालों में पानी की कमी नहीं होगी। इसके लिए पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलेगा।

भाजपा देश का संविधान बदलना चाहती है : कन्हैया कुमार

पटना । कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पटना में वक्फ कानून के विरोध में आयोजित की गई रैली को लेकर कहा कि यह प्रदर्शन हर उस नागरिक का है जो देश के संविधान पर विश्वास रखता है। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान कन्हैया कुमार ने भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा देश के संविधान को बदलना चाह रही है। इसी कड़ी में वक्फ कानून लाया गया है। यह कानून देखने में भले लग रहा हो, यह एक समुदाय का मामला है, लेकिन सही में यह मामला देश के सभी नागरिकों का मामला है। यही कारण है कि कांग्रेस वक्फ कानून का विरोध संसद से लेकर सड़क तक कर रही है। इस मामले को लेकर आगे भी जो संघर्ष होगा, इसमें पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ रहेगी। इधर, चुनाव आयोग के मतदाता पुनरीक्षण को लेकर कन्हैया कुमार ने कहा कि पहले आयोग यह मान ही नहीं रही थी कि कोई गड़बड़ी भी है। चुनाव आयोग इससे इंकार करता रहा है, लेकिन अब तो यह स्वीकार कर लिया कि गड़बड़ी है। गड़बड़ी के भी दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि जो भाजपा समर्थक वोटर हैं, उनका नाम जोड़ा जाता है और जो भाजपा विरोधी मतदाता हैं, उनका नाम हटाया जाता है।

3 जुलाई से शुरु हो रही अमरनाथ यात्रा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाई चौकियां

-तीर्थयात्रियों की जांच व सम्मानजनक व्यवहार के बीच संतुलन बनाने के निर्देश

जम्मू (एजेंसी)। अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा बल और प्रशासन तीर्थयात्रा से पहले निरीक्षण और ट्रायल रन कर रहे हैं। यह यात्रा 3 जुलाई को जम्मू-कश्मीर के बालटाल और पहलगाम से शुरू होगी। ऑनलाइन विंडो से चूकने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण जम्मू के विशेष केंद्रों पर शुरू हो गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं।

जम्मू के बेस कैंप यात्री निवास में रसद और प्रतिक्रिया प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए बसों को पूरी सुरक्षा के साथ भेजा गया है। तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को 2 जुलाई को औपचारिक रूप से जम्मू से रवाना किया जाएगा। तीर्थयात्रा से पहले सुरक्षा बलों और नागरिक प्रशासन की सुरक्षा और तैयारी सुनिश्चित की जा रही है। सुरक्षा इकाइयों की तत्परता और समन्वय का परीक्षण करने के लिए अभ्यास के दौरान बसों को पूर्ण सुरक्षा कवर के तहत भेजा गया। इस अभ्यास में भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे आपातकालीन परिदृश्यों का अनुकरण किया गया, जिसमें फंसे हुए तीर्थयात्रियों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया, निकासी और चिकित्सा सहायता पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस सिमुलेशन में फंसे हुए वाहनों को बचाना, घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार प्रदान करना और आपदा प्रतिक्रिया और सुरक्षा टीमों द्वारा एकीकृत प्रयासों के माध्यम से त्वरित राहत का समन्वय करना शामिल था।

हाल ही में सुरक्षा संबंधी धमकियों के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश कम नहीं है। एक तीर्थयात्री ने कहा कि मुझे अमरनाथ पर भरोसा है। आतंकवादी कुछ भी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। मैं लोगों से जम्मू-कश्मीर आने और यह दिखाने का आग्रह करता हूं कि हम डरे हुए नहीं हैं। जम्मू पुलिस ने 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए जांच चौकियां बनाई हैं।

पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जम्मू पुलिस ने जिले भर में रणनीतिक रूप से अहम कई स्थानों पर संयुक्त जांच चौकी स्थापित करके सुरक्षा व्यवस्था को काफी मजबूत कर दिया है। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रा को निर्बाध और सुरक्षित बनाने के लिए अर्द्धसैनिक बलों के साथ समन्वय में जांच चौकी स्थापित की गई हैं। ये चौकियां राष्ट्रीय राजमार्गों, जम्मू के आसपास और भगवती नगर आधार शिविर की ओर जाने वाले मार्गों सहित संवेदनशील और अत्यधिक व्यस्त आवाजाही वाले क्षेत्रों में 24 घंटे चालू रहेंगी। प्रवक्ता ने बताया कि सतर्कता और लोगों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जांच चौकियों की निगरानी कर रहे हैं।

अखिलेश ने बिना नाम लिए धीरेंद्र शास्त्री पर बोला हमला, करोड़ों में कथा सुनाते हैं और अंडर टेबल भारी भरकम रकम लेते

इटावा (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में कथावाचकों के साथ कथित रूप से जातिगत हमले की घटना ने यूपी का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरकर प्रसिद्ध कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि 'कथावाचक करोड़ों में कथा सुनाते हैं और अंडर टेबल भारी भरकम रकम लेते हैं।'

अखिलेश ने कहा कि धर्म को धंधा बना दिया गया है। एक व्यक्ति 50 लाख रुपये लेता है कथा के लिए। क्या किसी सामान्य व्यक्ति की इतनी हैसियत है कि वह बाबा को बुला सके?' उन्होंने सीधे-सीधे पं. धीरेंद्र शास्त्री का नाम लिए बिना उन्हें कटघरे में खड़ा किया। अखिलेश ने सवाल किया कि 'आप खुद पता करिए, वे पैसे लेते हैं या नहीं, और उनकी कथा की कीमत क्या होती है?'

सपा प्रमुख ने कहा कि यह घटना दिखाती है कि कुछ वर्ग कथा क्षेत्र पर वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। जो कथा कहने को व्यवसाय बना बैठे हैं, वहीं पिछड़े-दलितों को इसमें आने से रोकते हैं। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री ने सीधे अखिलेश यादव के आरोपों पर अब तक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इटावा घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कथा किसी जाति की बपौती नहीं है। अगर किसी ने कानून तोड़ा है, तब उस सजा कानून देगा, न कि भीड़। उन्होंने राजनीतिक नेताओं से अपील की कि 'धार्मिक मामलों को राजनीति का रंग न दिया जाए।' वहीं अखिलेश और धीरेंद्र शास्त्री समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर अब नए सिरे से बहस छिड़ गई है। जहां एक पक्ष बाबा पर कथावाचन को लेकर 'धंधा' चलाने का आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि 'धर्म प्रचारक पर राजनीति के लिए हमला हो रहा है।'

संक्षिप्त समाचार

समस्तीपुर में शख्स की संदिग्ध मौत : बीमार पति को पत्नी ने दी थी दवा

- शादी के बाद से ससुराल में रहता था

समस्तीपुर, एजेंसी। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सुरौली पंचायत के वार्ड-9 में संदिग्ध स्थिति में एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान उजियारपुर थाना क्षेत्र के लोहागीर गांव निवासी महेंद्र पासवान के बेटे उपेंद्र पासवान के रूप में की गई है। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। घटना के बाद ग्रामीण उसकी पत्नी को शक की नजर से देख रहे हैं।

20 साल पहले हुई थी शादी : बताया गया कि उपेंद्र शादी के बाद से ही अपने ससुराल सुरौली गांव में बस गए थे। उपेंद्र की शादी 20 साल पहले हुई थी। लोगों ने बताया कि दो-तीन दिन पहले उपेंद्र और उनकी पत्नी के बीच पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि घरेलू मामला होने के कारण बात सलट गई। इधर, उपेंद्र बीमार चल रहा थे। सुबह अचानक गांव के लोगों ने उनकी मौत की खबर सुनी। ग्रामीणों का कहना था कि मामला संदिग्ध है। पुलिस ने शव? को जब्त कर पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। पत्नी ने कहा कि बीमार थे, रात में उन्हें दवा दी गई है सुबह भी उन्हें दवा दी गई थी। करीब 4 : 30 बजे सुबह अचानक उनकी मौत हो गई।

आवेदन मिलने पर कार्रवाई होगी: विभूतिपुर थाना अध्यक्ष आनंद कश्यप ने कहा कि मामला संदिग्ध है। गांव के लोग उसकी पत्नी पर ही आरोप लगा रहे हैं। अभी किसी भी पक्ष की ओर से कोई आवेदन नहीं मिला है आवेदन मिलने के उपरांत इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कमियों को दूर करें, लक्ष्य प्राप्ति तक जुटे रहें

मुजफ्फरपुर, एजेंसी। आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान की ओर से आरडीएस कॉलेज के श्रीकृष्ण सभागार में शनिवार को हिन्दुस्तान प्रतिभा सम्मान 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक, इंटर, सीबीएसई व आईसीएसई के 10वीं एवं 12वीं के टॉपर्स बच्चों को सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त कर छात्र-छात्राएं काफी उत्साहित थे। असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है। यह सफलता की पहली सीढ़ी है। बच्चों को देखना है कि कहां कमी रह गई है। उसे दूर करें और अपने लक्ष्य प्राप्ति को लेकर लगतार जुटे रहें। आज की स्थिति काफी बदल गई है। अब ज्ञान और करियर के बारे में जानकारी लेने को कई संसाधन हैं। इनका प्रयोग करें। ये बातें शनिवार को आरडीएस कॉलेज स्थित श्रीकृष्ण सभागार में आयोजित 'हिन्दुस्तान के प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री सह मुजफ्फरपुर के सांसद डॉ. राजभूषण चौधरी ने कही। डॉ. चौधरी ने बच्चों और अभिभावकों से अपील की कि वे तकनीकी ज्ञान और रिसर्च से जुड़ें। इससे केवल मानव बल ही नहीं बल्कि समृद्ध युवाओं की फौज भी तैयार होगी।

3 साल में आधा काम, 4 प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुए पीएम की ड्रीम अमृत भारत स्कीम में लापरवाही

मुजफ्फरपुर, एजेंसी। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक (जीएम) छत्रसाल सिंह ने मुजफ्फरपुर जंक्शन का निरीक्षण किया। उन्होंने अमृत भारत योजना से चल रही 20 विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की। विश्वस्तरीय बन रहे जंक्शन का काम तीन वर्ष में अबतक 49.5 प्रतिशत हो सका है। चार प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सके हैं। जीएम ने निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के बाद जीएम ने सोनपुर मंडल और आरएलडीए के अधिकारियों संग जंक्शन के वीआइपी कक्ष में निर्माण की समीक्षा की। डीआरएम विवेक भूषण सूद ने उन्हें पीपीटी के माध्यम से पूरे प्रोजेक्ट की अद्यतन जानकारी दी। इसमें निर्माण में आ रहे व्यवधान के बारे में भी बताया गया। मालूम हो कि 442 करोड़ से मुजफ्फरपुर को विश्वस्तरीय जंक्शन बनाया जा रहा है। 21 सितंबर 2022 को इसका निर्माण शुरू और 20 सितंबर 2025 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। आएलडीए काम पूरा होने के लिए एक साल का एक्सटेंशन मांग चुका है। समीक्षा बैठक में डीआरएम के अलावा जोन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण/ उत्तर) राम जन्म, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आरएसपी) सुरेन्द्र कुमार, प्रधान मुख्य यांत्रिक

इंजीनियर आरआर प्रसाद, प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक इंदू रानी दूबे व अन्य थे।

पुनर्निर्माण के बाद बदल जाएगा प्रवेश व निकास द्वार

निरीक्षण के दौरान जीएम को डीआरएम ने पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी दी। बताया गया कि जंक्शन के पुनर्निर्माण के बाद स्टेशन का प्रवेश और निकास द्वार बदल जाएगा। यात्री एलिवेटेड रोड से जंक्शन पहुंचेंगे। नीचे से सभी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा कंबाइन्ड टर्मिनल को इमलीचट्टी सरकारी बस स्टैंड से एफओबी के माध्यम से जोड़ा जाएगा, ताकि यात्री बस स्टैंड से पैदल जंक्शन पहुंच सकें।

यात्री सुविधाओं, सौंदर्यीकरण को देखा

जीएम ने प्लेटफार्म विस्तार, यात्री सुविधाओं, सफाई व्यवस्था, स्टेशन सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्यों की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने स्टेशन पर नेम प्लेट, साइनबोर्ड लगाने को लेकर निर्देश दिये। पावर केबिन, कंट्रोल रूम, वाशिंग पिट, सिग्नलिंग सिस्टम और अन्य तकनीकी विभागों की व्यवस्था की भी समीक्षा की। कोचिंग काम्प्लेक्स और मालगोदाम क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद महाप्रबंधक सीतामढ़ी, रक्सौल, सुगौली के रास्ते चाम्पूधाम मोतिहारी के लिए रवाना हो गए।

पाटलिपुत्र-मुजफ्फरपुर खंड का किया विंडो निरीक्षण

पूर्मरे के जीएम छत्रसाल सिंह ने मुजफ्फरपुर में समीक्षा बैठक से पूर्व पाटलिपुत्र-मुजफ्फरपुर रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। महाप्रबंधक ने रेलखंड के मध्य स्टेशनों, रेल पुलों, रेलवे ट्रैक, ओएचई, सिग्नलिंग सिस्टम सहित यात्री सुविधाओं से जुड़े पहलुओं का जायजा लिया। उन्होंने संरक्षा पर विशेष बल देते हुए इसके प्रति अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। इस दौरान सोनपुर मंडल के डीआरएम विवेक भूषण सूद साथ में थे।

15 तक हर हाल में हो जाए सीटीबी में शिफ्टिंग

पुनर्निर्माण में चार प्रोजेक्ट का अबतक काम शुरू नहीं हो सका है। इसके लिए निर्माण एजेंसी को रेलवे ने जगह उपलब्ध नहीं कराई है। एमएलसीपी, एराइवल प्लाजा, एमएलसीपी को जोड़ने वाले एलिवेटेड रोड के संपर्क पथ और मुख्य स्टेशन बिल्डिंग के उत्तरी हिस्से में दूसरे भाग का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। जीएम ने प्लेटफॉर्म एक से तीन के प्रशासनिक कार्यालयों को 15 जुलाई तक कंबाइन्ड टर्मिनल बिल्डिंग में शिफ्ट करने का निर्देश दिया।

भागलपुर में निर्माणाधीन पुल की रेलिंग टूटकर नदी में गिरी

1600 करोड़ की लागत से बन रहा ब्रिज

भागलपुर, एजेंसी। भागलपुर में बिहपुर-वीरपुर एनएच-106 पर फुलौत को बिहपुर से जोड़ने के लिए 1600 करोड़ की लागत से बन रहे पुल की रेलिंग का कुछ हिस्सा शुक्रवार की देर रात क्षतिग्रस्त होकर नदी में गिर गया। घटना देर रात करीब ढाई बजे की है। इसके बाद निर्माण में जुटी कंपनी के अधिकारी व अभियंता मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू की। बताया गया कि बिहपुर की ओर से पुल पथ का भारी-भरकम 125 टन वजनी स्ट्रक्चर सेंगमेंट वाहन से फुलौत की ओर ले जाया जा रहा था। 90 चक्का वाला वाहन स्ट्रक्चर सेंगमेंट को लेकर नदी के ऊपर पुल को पार कर रहा था। तभी वाहन का प्रेसर पाइप फट गया।

इस कारण वाहन का संतुलन प्रभावित हुआ और भारी भरकम स्ट्रक्चर सेंगमेंट फिसलकर निर्माणाधीन पुल की करीब 40 मीटर रेलिंग को क्षतिग्रस्त करते हुए नदी में जा गिरा। जो सेंगमेंट वाहन पर लोड था, उसकी चौड़ाई करीब सात मीटर व लंबाई 30 मीटर बताई जा रही है। नवगछिया के एसडीओ ऋतुराज प्रताप सिंह ने बताया कि हमें जानकारी मिली है। जिस कंपनी को निर्माण कार्य का जिम्मा दिया गया है, उसके द्वारा ठीक कराया जाएगा। वहीं एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अभिषेक ने कहा कि निर्माण के दौरान हादसे होते हैं। हादसे की वजह की तकनीकी त्रुटि का पता किया जा रहा है। कोसी नदी पर हरियो त्रिमुहान के पास वोल्वो लोडर पर ले जा रहे सेगमेंट के दुर्घटना होने से एनएच 106 करीब 40 फीट क्षतिग्रस्त हुआ है। इस घटना में निर्माण एजेंसी के कर्मचारी बाल-बाल बच गए। गया।

महागठबंधन को ओवैसी का खुला ऑफर, बोले- अगर बिहार में एनडीए को रोकना है, तो साथ आएं

पटना, एजेंसी। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कवायद में जुटी है। पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के साथ उनकी बातचीत चल रही है। हालांकि महागठबंधन को लीड कर रहे तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस मामले पर कोई चर्चा नहीं हुई है। इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में इंडिया अलायंस को खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन बिहार में एनडीए की सत्ता में वापसी को रोकना चाहता है, तो हम साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन फैसला महागठबंधन के सहयोगी दलों को लेना है। अगर वो तैयार नहीं होते हैं। तो हमारी पार्टी सीमांचल के बाहर भी चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल

ईमान ने महागठबंधन के कुछ नेताओं से बात की है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम नहीं चाहते कि बिहार में भाजपा या एनडीए की सत्ता में वापसी हो। अब यह उन राजनीतिक दलों पर निर्भर है, जो एनडीए को बिहार में सत्ता में वापसी से रोकना चाहते हैं। 5 साल पहले, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी इसकी कोशिश की थी। लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इस बार भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह उन पर निर्भर है।

एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि अगर वो गठबंधन को तैयार नहीं होते हैं, तो हम सीमांचल और सीमांचल के बाहर भी चुनाव लड़ेंगे। मैं हर जगह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। आने वाले समय का इंतजार करें। सीटों की सटीक संख्या की घोषणा करना अभी जल्दबाजी होगी। हालांकि बहादुरगंज और ढाका की सीट के प्रत्याशियों का ऐलान कर चुका हूं।

इससे पहले ओवैसी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। आपको बता दें 2020 में एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जिसमें से पांच सीटें जीती थीं। हालांकि बाद में एआईएमआईएम के 4 विधायक राजद में चले गए थे। और अब सिर्फ एक मात्र विधायक अख्तरुल ईमान हैं। पार्टी को इन 20 सीटों पर डाले गए वोटों का 14.28त्न वोट मिला था। एआईएमआईएम ने जो पांच सीटें जीती थीं, वो सभी पूर्वी बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में आती हैं, जिसमें अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज सहित चार जिले शामिल हैं।

ढोली और कर्पूरीग्राम में बढ़ेगी प्लेटफॉर्म की लंबाई व ऊंचाई

मुजफ्फरपुर, एजेंसी। सोनपुर डीआरएम विवेक भूषण सूद और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रौशन कुमार ने शनिवार को ढोली व कर्पूरीग्राम स्टेशनों का औचक निरीक्षण किया।

यात्रियों को उपलब्ध सुविधाओं को देखा। निरीक्षण के बाद डीआरएम ने दोनों स्टेशनों के प्लेटफॉर्म की ऊंचाई और लंबाई बढ़ाने का निर्देश इंजीनियरिंग व कंस्ट्रक्शन विभाग के अधिकारियों को दिया। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के बैठने के लिए पर्याप्त छायादार जगह तैयार करने, दिव्यांग यात्रियों के लिए रैम्प, साइनेज बोर्ड लगाने का निर्देश दिया।

पटना में धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम को नहीं मिली प्रशासन की अनुमति

पटना, एजेंसी। कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य पंडित धीरेंद्र शास्त्री, तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य समेत कई जाने माने संत छह जुलाई को पटना आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भीड़ नियंत्रण और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से ऐसे कार्यक्रम की कोई अनुमति नहीं दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि पिछली बार पंडित धीरेंद्र शास्त्री के नौबतपुर कार्यक्रम के दौरान काफी भीड़ हो गई थी। इसे लेकर प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। इस संबंध में अधिकारियों की टीम गठित हो सकती है, जो भीड़ प्रबंधन और विधि व्यवस्था की दृष्टिकोण से संत समागम के समय शहर की क्या स्थिति हो सकती है इस पर रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के बाद ही अनुमति निर्णय लेगा। जिला प्रशासन का कहना है कि गांधी मैदान में कितनी भीड़ होगी व विधि व्यवस्था को लेकर क्या समस्या हो सकती है इसका आकलन करने के बाद ही अनुमति देने पर निर्णय होगा। प्रशासन का कहना है कि जिला नियंत्रण कक्ष को विभिन्न श्रोतों से यह जानकारी

मिली है कि छह जुलाई को आचार्य धीरेंद्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम समेत कई संत गांधी मैदान में संत समागम करने वाले हैं। इससे पहले मई 2025 में मुजफ्फरपुर आए थे, जहाँ उन्होंने एक विशाल यज्ञ में भाग लेकर कथा वाचन किया था। उनके पहले पटना के तरेत पाली मठ में सात दिवसीय यज्ञ का आयोजन हुआ था, जहां पांच दिनों तक उन्होंने कथा की थी। बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने अपने पिछले दौरे में कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

छपरा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर कोर्ट का स्टे

छपरा, एजेंसी। छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में वीआईपी लेन पर बने विवादित मकान को लेकर न्यायिक कार्रवाई शुरू हो गई है। छपरा व्यवहार न्यायालय ने नगर आयुक्त के तोड़फोड़ आदेश पर रोक लगा दी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हाकियत वाद संख्या 333/2025 की सुनवाई हुई। यह मामला चंद्रभूषण पांडे बनाम नगर आयुक्त का है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रतिवादियों की उपस्थिति और जवाब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। नगर आयुक्त का आरोप है कि चंद्रभूषण पांडे ने वीआईपी लेन में सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने यहां करकट का शेड और पक्का मकान बना लिया है।

कागजात पेश नहीं करने पर कार्रवाई

नगर निगम ने उन्हें दस्तावेज दिखाने का मौका दिया था। लेकिन वे निर्धारित समय पर न तो कार्यालय पहुंचे और न ही कोई कागजात पेश किए। इसके बाद नगर आयुक्त ने निर्माण हटाने का आदेश दिया। उन्होंने एसडीओ सदर से मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मांग भी की थी।

चंद्रभूषण पांडे ने की अंतरिम राहत की मांग

इससे पहले ही चंद्रभूषण पांडे कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने अंतरिम राहत की मांग की। कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को शो कॉज नोटिस भेजा। नोटिस की तामीली हो चुकी है। लेकिन प्रतिवादी कोर्ट में नहीं पहुंचे। कोर्ट ने आदेश दिया कि विस्तृत सुनवाई तक यथास्थिति बनाई रखी जाए। अब यह मामला प्रशासनिक कार्रवाई और न्यायिक निर्णय के बीच फंस गया है।

बिहार आकर मुझे बहुत अच्छा लगा : मल्लिका शेरावत

मुजफ्फरपुर, एजेंसी। इमली चट्टी स्थित लिच्छवि बिहार कैंपस में शनिवार को बनारसी बाबू कैफे का उद्घाटन फिल्म अभिनेत्री मल्लिका शेरावत ने किया। इस मौके पर बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, मेयर निर्मला साहू और डिप्टी मेयर मोनालिसा भी मौजूद रहीं। डॉ. बसंत सिंह और ज्योति सिंह ने संयुक्त रूप से अतिथियों को पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र और प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया। कैफे के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. बसंत ने बताया कि यह शहर का पहला कैफे होगा, जहां शहरवासी बिहार के प्रसिद्ध व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। एक ही छत के नीचे लोग रेस्टोरेंट्स और कैफे की सुविधा का मजा ले सकेंगे। फिल्म अभिनेत्री मल्लिका शेरावत ने कहा कि बिहार आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहां के लोग बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि आप बनारसी बाबू कैफे में आइये और इसके लजीज व्यंजनों, खासकर बनारसी कचौड़ी, जलेबी और सब्जी का आनंद लीजिए। अभिनेत्री को देखने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। यातायात को नियंत्रित करने के लिए डीएम आवास से इमलीचट्टी तक की सड़क को बंद कर दिया गया था। इस मौके पर यश सिंह, आद्या सिंह, खुशी सिंह, डॉ. राजेश सिंह, डॉ. कश्यप संतोष, प्रभात मेहता, प्रतीक सिंह, डॉ. पीके द्विवेदी आदि उपस्थित रहे।

बिहार के 6 जिलों में होगा पत्थर खनन

राजस्व और रोजगार दोनों मिलेगा, डीएसआर रिपोर्ट तलब

पटना/भागलपुर, एजेंसी। बिहार में पत्थर की मांग और झारखंड पर निर्भरता घटाने के लिए प्रदेश में भी पत्थरों का खनन होगा। इसको लेकर खान एवं भूतत्व विभाग ने तैयारी शुरू की है। पहले फेज में राज्य के छह जिलों में पत्थरों के खनन का निर्णय लिया गया है। विभाग ने बांका, गयाजी, नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद और कैमूर की पहाड़ियों को पत्थर भूखंड के लिए चिह्नित किया है। मुख्य सचिव ने इन जिलों के समाहर्ताओं से जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन मांगा है।

भागलपुर से सटे में बांका में यदि पत्थर खनन की अनुमति मिली तो प्रमंडल स्तर पर बालू के बाद राजस्व संग्रहण का सबसे बड़ा जिला बन जाएगा। इस फेज में भागलपुर को अलग रखा गया है। बताया गया कि भागलपुर की पहाड़ियों में खनिज तत्व छिपे होने के संकेत मिले हैं। इसलिए यहां इजाजत नहीं दी गई है। बांका के खनिज विकास पदाधिकारी कुमार रंजन ने बताया कि भागलपुर-मुंगेर जिला सीमा पर स्थित शंभूगंज अंचल के पहाड़ी मौजा को चिह्नित किया गया है। यह पहाड़ी करीब 20 एकड़ में फैला हुआ है। इसके खनन की अनुमति मिली तो करीब सात मिलियन टन पत्थर की प्राप्ति होगी। जिससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपये बतौर राजस्व मिलेगा। साथ ही स्टोन क्रशर मशीनों की स्थापना से हजारों लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी सिर्फ दो जिले में ही खनन की अनुमति है। मुंगेर प्रमंडल के शेखपुरा और मगध प्रमंडल के गयाजी में स्टोन क्रशर की अनुमति है इधर, विभाग के जानकार बताते हैं कि वर्ष 2002 से पहले बिहार के 13 जिलों में लीज होल्ड पत्थर खदानें चल रही थीं।

राज्य के भागलपुर, बांका, बेतिया, जमुई, शेखपुरा, नालंदा, भभुआ, नवादा, मुंगेर, रोहतास, जहानाबाद और औरंगाबाद में कई क्रशर मशीनें थीं। लेकिन इन सभी जिलों में पत्थर तोड़ने वाली मशीनों की संख्या सीमित कर दी गई। खान एवं भू-विज्ञान मंत्रालय ने उस वक्त पत्थर उत्खनन के लिए 351 पट्टे दिए थे।

क्रशर से जुड़े लोगों ने बताया

जो बिहार के 13 जिलों में 993 एकड़ पहाड़ी भूमि को कवर करते थे। क्रशर से जुड़े लोगों ने बताया कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने वर्ष 2021 में स्टोन

क्रशर इकाई के संचालन के दौरान धूलकणों को आस-पास फैलने से रोकने के लिए स्टोन क्रशर इकाइयों को 12 फीट ऊंची दीवार बनाना अनिवार्य कर दिया। बोर्ड ने जल छिड़काव की स्थायी व्यवस्था के लिए चाहरदीवारी के साथ चारों ओर स्थायी पाइप लाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा था।

ट्रम्प के बिग ब्यूटीफुल बिल को चर्चा की मंजूरी: सीनेट में 51-49 वोटों से प्रस्ताव पारित

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बिग ब्यूटीफुल बिल को चर्चा के लिए मंजूरी दे दी है। शनिवार देर रात हुई वोटिंग में सीनेट ने 51-49 वोटों के अंतर से एक प्रस्ताव पारित किया, जिससे सदन को बिल पर बहस शुरू करने की इजाजत मिल गई। दो रिपब्लिकन सीनेटरों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। वोटिंग के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद थे। क्योंकि टाई की स्थिति में उनके वोट करने की जरूरत पड़ सकती थी। ट्रम्प टैक्स और खर्च में कटौती करने वाले इस बिल को 4 जुलाई से पहले पारित कराना चाहते हैं।

टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ इलॉन मस्क ने ट्रम्प के बिग ब्यूटीफुल बिल की एक बार फिर से आलोचना की है। मस्क ने शनिवार को एक्स पर लिखा, ट्रम्प का यह बिल अमेरिका में लाखों नौकरियां खत्म कर देगा और हमारे देश को बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान पहुंचाएगा। मस्क ने कहा, यह पूरी तरह से पागलपन भरा और विनाशकारी है। यह कानून पुराने उद्योगों को रियायत देता है, लेकिन भविष्य के उद्योगों को तबाह कर देगा। मस्क ने पिछले महीने इस बिल को लेकर ट्रम्प प्रशासन में गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था।

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में फाइनल वोटिंग होगी करीब 940 पन्नों का बिग

ब्यूटीफुल बिल शुक्रवार देर रात जारी किया गया था। इस पर हफ्ते के अंत तक बहस जारी रहने की उम्मीद है, जिसमें कई संशोधन और मतदान होंगे। अगर सीनेट बिल को पास कर देता है, तो यह फाइनल वोटिंग के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वापस आएगा। इसके बाद व्हाइट हाउस में ट्रम्प की मंजूरी के लिए जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी के पास दोनों सदनों में बहुमत है। हालांकि, डेमोक्रेट्स के अलावा रिपब्लिकन पार्टी के कुछ अपने नेता ही बिग ब्यूटीफुल बिल का विरोध कर रहे हैं। यह बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 22 मई को सिर्फ 1 वोट के अंतर से पास हो चुका है। इसके समर्थन में 215 और विरोध में 214 वोट मिले थे।

बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर भिड़े थे मस्क और ट्रम्प : ट्रम्प और मस्क 'बिग ब्यूटीफुल बिल' को लेकर आमने-सामने आ गए थे। ट्रम्प इस बिल के समर्थन में हैं, जबकि मस्क खिलाफ। ट्रम्प का दावा है कि यह 'देशभक्ति से भरा हुआ' कानून है। इसके पारित होने से अमेरिका में निवेश बढ़ेगा और चीन पर निर्भरता घटेगी। जबकि मस्क इसे पोर्क फिल्ड यानी कि बेकार खर्चों से भरा बिल मानते हैं।

ट्रम्प ने मस्क को पागल बताया, तो मस्क बोले ट्रम्प एहसान फरामोश : ट्रम्प और मस्क के बीच 5 जून को बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर बहस तब शुरू हुई जब ट्रम्प ने मीडिया से बात करते हुए मस्क को लेकर नाराजगी जताई थी। ट्रम्प ने कहा था कि जब हमने अनिवार्य तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के कानून में कटौती करने की बात कही तो मस्क को दिक्कत होने लगी। मैं इलॉन से बहुत निराश हूं।

मैंने उनकी बहुत मदद की है। इसके बाद मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रम्प को एहसान फरामोश बताते हुए लगातार कई ट्वीट किए। मस्क ने कहा कि मैं नहीं होता तो ट्रम्प चुनाव हार जाते। उन्होंने ट्रम्प पर महाभियोग चलाने तक की बात कही थी। इसके बाद ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर मस्क को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा- जब मैंने उनका ईवी मैंडेट (कानूनी आदेश) वापस लिया तो मस्क पागल हो गए। ट्रम्प ने मस्क की कंपनी को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने की धमकी दी थी।

सर्बिया में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, एक हादसा सरकार के गले की हड्डी बना

बेलग्राड, एजेंसी। यूरोपीय देश सर्बिया में अपनी ही सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शनिवार को भारी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन के लिए राजधानी बेलग्राड में सड़कों पर उतरे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि देश में जल्द चुनाव कराए जाएं। हालांकि अभी सर्बियाई सरकार का कार्यकाल 2027 तक है, लेकिन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसके चलते लोग नाराज हैं। दरअसल आठ माह पहले सर्बिया में एक ट्रेन स्टेशन की छत गिर गई थी, जिसमें दबकर 16 लोगों की मौत हो गई थी। लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ और सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुसिस को पद छोड़ना चाहिए। हालांकि बीते 12 साल से सर्बिया की सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुसिस इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि अब लोगों ने जल्द चुनाव कराने की मांग शुरू कर दी है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों का नेतृत्व विश्वविद्यालय के छात्र कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन अब देश के कई हिस्सों में फैल गए हैं। विरोध बढ़ता देख इस साल की शुरुआत में सर्बिया के प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविक ने पद छोड़ दिया था। राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुसिस की पार्टी के पास सर्बिया की 250 सीटों में से 156 सीटें हैं।

इजरायली एयरस्ट्राइक में मारा गया हमास का टॉप लीडर

येरूशलम, एजेंसी। इजरायली रक्षा बल, आईडीएफ ने एक बड़ी जानकारी दी है और दावा किया है कि इजरायली सैनिकों ने गाजा सिटी के सबरा इलाके में एक टारगेटेड एयरस्ट्राइक के जरिए हमास के टॉप कमांडर हाकम मोहम्मद इस्सा अल-इस्सा को मार गिराया है। आईडीएफ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है जिसके मुताबिक हमास का टॉप कमांडर अल-इस्सा इजरायल में हुए 7 अक्टूबर 2023 के नरसंहार का मास्टरमाइंड था, आतंकियों को ट्रेनिंग देता था और हमास के सैन्य विंग के संस्थापक सदस्यों में से एक था। आईडीएफ ने ट्वीट पर जारी किए गए अपने बयान में कहा है, टॉप कमांडर हाकम मोहम्मद इस्सा अल-इस्सा हमास की सैन्य ताकत बढ़ाने, आतंकियों को प्रशिक्षण देने का काम करता था और वह सात अक्टूबर के हमले में हुए नरसंहार की पूरी योजना बनाने में मुख्य भूमिका निभा रहा था। आईडीएफ ने कहा है, अल इस्सा हमास की वायु और नौसेना हमलों की योजनाओं में भी अहम भूमिका निभा चुका था, वह मारा जा चुका है। आईडीएफ और इजरायली सुरक्षा एजेंसी आईएसए ने बताया है कि, हम अभी सात अक्टूबर 2023 में हुए हमले में शामिल सभी आतंकियों को ढूंढ-ढूंढकर खत्म करने के अभियान को आगे भी जारी रखेंगे।

जानिए कौन था मुहम्मद इस्सा अल इस्सा : हमास का टॉप कमांडर मुहम्मद इस्सा अल इस्सा हमास के जनरल सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य, ट्रेनिंग हेडक्वार्टर का प्रमुख और अल-क़सम ब्रिगेड्स की मिलिट्री एकेडमी का सह-संस्थापक भी था, जहां वह कथित तौर पर हजारों आतंकियों को प्रशिक्षण देने और तकनीकी क्षमता विकसित करने में लगा हुआ था। अल-इस्सा के बारे में आईडीएफ ने बताया है कि उसने सीरिया और इराक में युद्ध की ट्रेनिंग ली थी और साल 2005 में सीरिया से गाजा आया था, जहां वह हमास के सैन्य संगठन का अहम हिस्सा बन गया था।

बफेट ने छह अरब डॉलर के शेयर किए दान; शीर्ष अमीरों की सूची में एक स्थान पिछड़े दिग्गज निवेशक

वाशिंगटन, एजेंसी। अरबपति निवेशक वॉरेन बफेट ने शुक्रवार को अब तक का सबसे बड़ा सालाना दान दिया। इसके तहत उन्होंने छह अरब डॉल (लगभग 51,300 करोड़ रुपये) मूल्य के बर्कशायर हैथवे शेयर पांच चैरिटी संस्थाओं को दान किए। इनमें सबसे अधिक दान पाने वालों में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और उनके परिवार के चलाए जाने वाले चार फाउंडेशन भी शामिल हैं।

हालांकि,बफेट ने पहले ही साफ कर दिया है कि उनकी मौत के बाद गेट्स फाउंडेशन को दान समाप्त हो जाएगा। बफेट ने इस साल कुल 12.36 मिलियन क्लास बी बर्कशायर हैथवे शेयर दान किए। इससे 2006 से अब तक उनका कुल दान 60 अरब डॉलर (करीब 5.13 लाख करोड़ रुपये) के पार हो पहुंच गया है। इस साल उन्होंने गेट्स फाउंडेशन को 94.3 लाख शेयर, सुसान थॉम्पसन बफेट फाउंडेशन को 943,384 शेयर के साथ अपने तीन बच्चों हॉवर्ड, सूसी और पीटर की चलाई जा रही हॉवर्ड जी बफेट फाउंडेशन, शेरवुड फाउंडेशन और नोवो फाउंडेशन को 6,60,366 शेयर दान किए। इस दान के बाद भी बफेट के पास बर्कशायर हैथवे के 13.8 फीसदी शेयर बने हुए हैं।

ईरानी विदेश मंत्री की ट्रम्प को चेतावनी: कहा- खामेनेई के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल बंद करें, तभी कोई समझौता होगा

तेहरान, एजेंसी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को चेतावनी दी है कि वे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल बंद करें। अराघची ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ट्रम्प का यह रवैया न सिर्फ खामेनेई का बल्कि उनके लाखों समर्थकों का भी अपमान करता है। ट्रम्प अगर ईरान से कोई समझौता चाहते हैं तो उन्हें अपनी भाषा बदलनी होगी। अराघची का यह बयान ट्रम्प के उस दावे के बाद आया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि उन्होंने खामेनेई को मरने से बचाया, नहीं तो उनकी बहुत बुरी मौत होती।

इजराइल पर भी कसा तंज : अराघची ने इजराइल पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि जब ईरानी मिसाइलें गिरती हैं तो इजराइल डर के मारे 'डैडी के पास भागने' को मजबूर हो जाता है। ट्रम्प को पहली बार नाटो चीफ मार्क रूटे ने मजाकिया अंदाज में 'डैडी' कहा था। दरअसल, ट्रम्प इजराइल और ईरान पर सीजफायर तोड़ने को लेकर नाराज थे। इस दौरान उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल कर दिया था। इसके जवाब में नाटो चीफ ने मजाक में कहा, डैडी को कभी-कभी कठोर भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि उन्हें रोका जा सके। बाद में यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ट्रम्प बोले थे- मैंने खामेनेई को भयानक मौत से बचाया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के उस दावे को झूठा करार दिया, जिसमें उन्होंने इजराइल के खिलाफ

जंग में जीत की ऐलान किया था। ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर कहा था- मैंने खामेनेई को एक भयानक और अपमानजनक मौत से बचाया। मुझे यह भी उम्मीद नहीं है कि वे मुझे शुक्रिया कहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि वह खामेनेई के ठिकाने से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने इजराइल और अमेरिकी सेना को उनकी हत्या से रोका, जिससे उनकी जान बच गई। उन्होंने आगे कहा, ईरान ग्लोबल सिस्टम में शामिल होने की जगह गुस्सा और दुश्मनी दिखा रहा है, जिसकी वजह से उनकी सेना, इकोनॉमी और भविष्य बर्बाद हो चुका है। इजराइली रक्षा मंत्री ने भी कहा था- खामेनेई को मारना चाहते थे इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने गुरुवार को कहा था कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म करना चाहता था। काट्ज ने चैनल 13 के साथ एक इंटरव्यू में कहा, अगर खामेनेई हमारी पहुंच में होते, तो हम उन्हें मार गिराते। काट्ज ने कहा, इजराइल खामेनेई को खत्म करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने का कोई मौका नहीं था। काट्ज से जब पूछा गया कि क्या इजराइल ने अमेरिका से इसकी इजाजत मांगी थी, इस पर उन्होंने कहा, हमें इन चीजों के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। इजराइल से जंग में मारे गए 60 ईरानी अफसरों का शनिवार को अंतिम संस्कार किया गया। इनमें 30 सैन्य कमांडर्स और 11 परमाणु वैज्ञानिक शामिल थे। तेहरान में इनके जनाजे में हजारों लोगों की भीड़ जुटी। जिन लोगों को दफनाया गया, उनमें ईरान के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी मोहम्मद बाघेरी भी शामिल थे। वे ईरानी आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ थे। अफसरों के शवों को गाड़ियों पर ईरानी झंडे में लिपटे ताबूतों में रखे थे। ताबूतों के साथ अफसरों की तस्वीरें भी रखी थीं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची, पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कलीबाफ, ज्युडिश्यरी चीफ मोहसेनी-एजेई, आईआरजीसी कुद्स फोर्स कमांडर इस्माइल कानी सहित कई बड़े नेता और सैन्य अधिकारी भी जनाजे में पहुंचे।

पेज एक का शेष...

कांवड़ मार्ग में स्थित...

संरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ आर. राजेश कुमार ने कहा कांवड़ यात्रा के दौरान पंडालों, भंडारों और अन्य भोजन केंद्रों पर परोसे जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मिलावटखोरों और मानकों से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों की सेहत हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

खाद्य पदार्थों की सघन जांच का अभियान-खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की विशेष टीमें हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों में तैनात की गई हैं। ये टीमें नियमित रूप से पंडालों से दूध, मिठाई, तेल, मसाले, पेय पदार्थ आदि के नमूने लेंगी और जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजेंगी। अगर कोई नमूना मानकों पर खरा नहीं उतरता तो संबंधित स्थल को तत्काल बंद कर दिया जाएगा।

आपदा प्रभावितों....

देहरादून कांवली में दैवीय आपदा के कारण अरविन्द पुत्र प्रेम लाला की मृत्यु होने पर उनके पत्नी मीना देवी को 4.00 लाख की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की गई। गढ़ी में पक्का भवन आंशित क्षति होने पर प्रभावित अमित कुमार शर्मा को रु.11500, रिखौली में कच्चा भवन आंशिक क्षति पर सविता देवी, अर्पित बिष्ट को 4-4 हजार, योगेश क्षेत्री तथा घंघोड में भक्त बहादुर को उनका पक्का भवन आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर 6500 की अहैतुक सहायता चेक प्रदान किया गया।

ब्रहमपुरी लोहिया नगर में कच्चे भवन आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर सरालीन, सागीर, नूरजहॉ व सत्तार अहमद को प्रति व्यक्ति 2500 रुपये की अहेतुक सहायत दी गई। बनिया बाजार बीरपुर में रेखा भण्डारी, मोहिनी शाही, रितिका कन्नौजिया, कुसुम वर्मा, पूजा शर्मा, कोमल, वीर बहादुर, अतुल, दल बहादुर को 5-5 हजार की सहायता धनराशि के चेक वितरित किए गए। जाखन में पक्का भवन क्षतिग्रस्त होने पर अशरफ अली व किशन थापा को 11500 की सहायता राशि प्रदान की गई। सरौना में कच्चा आवसीय भवन आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर प्रभावित रणवीर सिंह को 4 हजार की अहैतुक सहायता प्रदान की गई। जिलाधिकारी सविन बंसल ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि सभी तहसीलों में आपदा प्रभावित क्षेत्रों को विस्तृत आंकलन करते हुए प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव...

कार्मिकों का चयन किया। इसमें पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारी शामिल है। देहरादून जनपद के 06 विकास खंडों में कुल 1090 मतदेय स्थल है। पहले रेंडमाइजेशन के तहत 1512 मतदान दल बनाए गए है, जिसमें 7560 कार्मिकों का चयन किया गया है। चयनित पीठासीन अधिकारियों को 06 जुलाई और प्रथम मतदान अधिकारियों को 07 जुलाई को पहला प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतदान कार्मिकों के दूसरे रेंडमाइजेशन में पार्टी गठन के साथ ब्लॉक आवंटित किए जाएंगे। प्रत्येक पोलिंग पार्टी में द्वितीय कार्मिक के रूप में महिला कार्मिक की भी तैनाती की जाएगी।

पारदर्शिता के लिए रेंडमाइजेशन प्रक्रिया की पूरी वीडियो एवं फोटोग्राफी भी की गई। कार्मिकों के रेंडमाइजेशन के दौरान जिला सूचना विज्ञान अधिकारी रणजीत सिंह चौहान, एडीआईओ अंकुश पांडेय, डीटीडीओ बृजेन्द्र पांडेय आदि मौजूद थे।

मेडिकल फैकल्टी के लिये बनेगी...

बेहतर बनाने के लिये सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात चिकित्सकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है साथ ही उनके मानदेय में भी बढ़ोत्तरी की जायेगी। ताकि अधिक से अधिक चिकित्सकों को पहाड़ में सेवाएं देने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके। कार्यक्रम में डॉ. रावत ने चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले चिकित्सकों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में कुलपति हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ओंकार सिंह, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आशुतोष सयाना, प्राचार्य दून मेडिकल कॉलेज डॉ. गीता जैन सहित विभागीय अधिकारी, मेडिकल प्रोफेशनल्स एवं मेडिकल छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

डॉक्टर्स डे के उपलक्ष में प्रदेश के 25 प्रतिष्ठित डॉक्टर का सम्मान

गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का आयोजन

♦स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सकों के लिए की पांच बड़ी घोषणाएं

देहरादून(ब्यूरो)। नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित ष्डॉक्टर ऑफ द ईयरष् सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार इसी वर्ष से ष्डॉक्टर ऑफ द ईयरष् की तर्ज पर मेडिकल फैकल्टी के लिए 05 चरक अवार्ड और उत्कृष्ट डॉक्टर के लिए 05 सुश्रुत अवार्ड प्रारंभ करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अवार्ड के लिए राज्य सरकार 1,00,000/-, 75000/- और 50000/- और 25- 25 हजार रुपए की धनराशि भी प्रदान करेगी। इसके साथ ही जिन डॉक्टर को और मेडिकल फैकल्टी को यह अवार्ड प्राप्त होगा उनको ट्रांसफर के मामले में 2 वर्ष की छूट भी प्रदान की जाएगी और साथ ही एक वर्ष के लिए अध्ययन हेतु विदेश भेजने की व्यवस्था करने की घोषणा की।

राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के उपलक्ष पर गर्वनमेंट दून मंडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में 'डॉक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड- 2025' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, विशिष्ट अतिथि पद्म श्री डॉ. बी. के. एस. संजय एवं अध्यक्ष डॉ. ओंकार सिंह थे। इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ अरुण त्रिपाठी, चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ आशुतोष सयाना तथा दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ गीता जैन भी मंचासीन थे।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अपने संबोधन में कहा कि 2025 के अंत तक सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सभी पदों में नियुक्ति हो जाएगी। साथ ही पदोन्नति को भी शत प्रतिशत पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टर्स का एक अलग से काडर

बनाया जाएगा तथा पर्वतीय भत्ता 50 प्रतिशत किया जाएगा। उन्होंने इस वर्ष के अंत तक सभी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल फैकल्टी के लिए शत प्रतिशत आवास बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने चिकित्सकों तथा मेडिकल फैकल्टी के ट्रांसफर के लिए अलग से ट्रांसफर नीति लाने की घोषणा भी की, जिसमें एक व्यक्ति एक पद पर एक जगह 03 वर्ष से अधिक नहीं रहेगा।

मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पूरे प्रदेश से चयनित 25 उत्कृष्ट डॉक्टर को इस वर्ष का ष्डॉक्टर ऑफ द ईयरष् अवार्ड प्रदान किया।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पद्म श्री डॉ. बी. के. एस. संजय ने कहा कि आज सड़क दुर्घटनाएं विकलांगता का मुख्य कारण है। सड़क दुर्घटनाओं ने प्रदेश में तबाही मचा रखी है। हर साल लगभग 1500 दुर्घटनाएं होती है जिनमें 1000 लोगों की मौत हो जाती है। डॉ. संजय ने मुख्य अतिथि माननीय स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत जी से अनुरोध किया कि सड़क सुरक्षा स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो यह न केवल प्रदेश बल्कि देश के हित में ऐतिहासिक कदम होगा।

कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉ. ओंकार सिंह ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य का इतना व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए कि समाज का एक तबका इसका लाभ ही ना ले सके। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ अरुण त्रिपाठी ने स्वस्थ जीवन एवं सफल इलाज में आयुष चिकित्सा के महत्व को रेखांकित किया। चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखंड के निदेशक, डॉ. आशुतोष सयाना ने कहा कि चिकित्सकों को कुछ हद तक निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए और समाज को उनके सेवा भाव की सराहना करनी चाहिए। कार्यक्रम को दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ गीता जैन ने भी संबोधित किया। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम के अन्य अतिथियों ने भी चिकित्सकों के योगदान की सराहना की। कार्यक्रम का स्वागत संबोधन आयोजन सचिव एवं दिव्य हिमगिरि के संपादक कुँवर राज अस्थाना ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन एचएनबी उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी के कुलसचिव डॉ आशीष उनियाल ने दिया। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने डॉ ऋचा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए न बी उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओंकार सिंह ने चिकित्सकों के महत्व और चिकित्सा शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। विशिष्ट अतिथि पदम श्री डॉक्टर बी के एस संजय ने अपने संबोधन में डॉक्टर के साथ नर्स एनेस्थेटिक और लब टेक्निशियन की भूमिका को रेखांकित किया।

विशिष्ट अतिथि आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण त्रिपाठी ने चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद के महत्व को रेखांकित किया निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर आशुतोष राणा ने बताया कि किस तरह से चिकित्सक को अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए मरीज की सेवा करनी है उसे सेवा का फल ईश्वर के हाथ में है।

राजकीय दूध मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने आज के दिन के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया की किस तरह से देश में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की शुरुआत हुई। इससे पूर्व अपने स्वागत संबोधन में कार्यक्रम के आयोजन एवं दिव्या हिमगिरि के संपादक कुंवर राज स्थान ने कार्यक्रम के विषय के बारे में बताया और इस वर्ष चयनित डॉक्टरों की प्रक्रिया और पूर्व के कार्यक्रमों के बारे में बताया।

कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रिचा ने किया एवं वोट आफ थैंक्स एचएनबी उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर आशीष उनियाल ने दिया। कार्यक्रम के अंत में डॉ आशीष उनियाल एवं कंवर राज अस्थाना ने मंचासीन सभी अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया।

इनको सम्मानित किया गया

1. डॉ. अनुराग रावत, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जॉलीग्रांट
2. डॉ. जयंती सेमवाल, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जॉलीग्रांट
3. डॉ. गुरजीत खुराना, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जॉलीग्रांट
4. प्रो. (डॉ.) चंद्र शेखर, राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार
5. डॉ. ओमना चावला, राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार
6. डॉ. डी.के. टम्टा, वीसीएसजी राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर (गढ़वाल)
7. डॉ. दीपा हटवाल, वीसीएसजी सरकारी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर (गढ़वाल)
8. प्रो. (डॉ.) वरुण कुमार, सीमा डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल, ऋषिकेश,
9. डॉ अंजुम सैयद, एम्स ऋषिकेश
10. डॉ. शैलेन्द्र हांडू, एम्स ऋषिकेश
11. डॉ. मोहित ढींगरा, एम्स ऋषिकेश
12. डॉ. अजय कुमार गुप्ता, ऋषिकुल परिसर, यूएयू, हरिद्वार
13. डॉ. ज्ञानेंद्र दत्त शुक्ल, गुरुकुल परिसर, यूएयू, हरिद्वार।
14. डॉ. मन्नत मरवाहा, हर्रावाला कैम्पस, यूएयू, देहरादून
15. डॉ. (लेफ्टिनेंट कर्नल) राहुल शुक्ला, गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय
16. डॉ. (श्रीमती) सविता गोयल, सविता पैथोलॉजी सेंटर
17. डॉ. पंकज अरोड़ा, श्री महंत इंद्रेश अस्पताल और एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज, 18. डॉ तृप्ति ममगाईं, श्री महंत इंद्रेश अस्पताल और एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज, 19. डॉ. उत्कर्ष शर्मा, श्री महंत इंद्रेश अस्पताल और एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज, 20. डॉ.अखिलेश पांडे, ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, 21. डॉ. उषा रावत, राजकीय अल्मोडा मेडिकल कॉलेज, 22. डॉ. अशोक कुमार, राजकीय अल्मोडा मेडिकल कॉलेज, 23. डॉ. अभय, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून, 24. डॉ.वंदना बिष्ट, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून, 25. डॉ शिव यादव, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून।

पहलगाम आतंकी हमले पर क्वाड ने भारत के समर्थन में बड़ा बयान दिया

नई दिल्ली: अमेरिका के वॉशिंगटन में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की एक सुर में निंदा की। क्वाड की इस बैठक में शामिल चारों सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने इस घटना को निंदनीय बताया। क्वाड के विदेश मंत्रियों के संयुक्त बयान में कहा गया कि क्वाड सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा जिनमें सीमापार आतंकवाद भी शामिल है। हम इसकी सभी प्रारूपों में निंदा करते हैं और आतंकवाद से निपटने में सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता जताते हैं। हम 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं जिसमें 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई थी जबकि कई घायल हुए थे। ।

हम इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्तपोषकों को बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाने

की मांग करते हैं और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से आह्वान करते हैं कि वे अंतरराष्ट्रीय कानून और संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के तहत अपने दायित्वों के अनुसार इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करें।

क्वाड के विदेश मंत्रियों के संयुक्त बयान में कहा गया कि हम, अमेरिका के विदेश मंत्री और ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के विदेश मंत्रियों ने एक जुलाई को वॉशिंगटन में मुलाकात की। इस दौरान हमने अधिक खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई। हम कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताते हैं। बयान में कहा गया कि इंडो पैसिफिक में चार प्रमुख समुद्री शक्तियों के तौर पर हमें विश्वास है कि समुद्री क्षेत्र में शांति और स्थिरता इस क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि का आधार है। हम एक ऐसे क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां सभी देश दबाव से मुक्त हों और हम किसी भी एकतरफा कार्रवाई का दृढ़ता से विरोध करते हैं जो बल या दबाव द्वारा यथास्थिति को बदलने का प्रयास करती हो। दरवाजा खटखटाया संयुक्त बयान में कहा गया कि हमने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की और क्वाड की ताकतों व संसाधनों का उपयोग क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कैसे किया जा सकता है, इस पर विचार किया। क्वाड के दीर्घकालिक प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए हम आज एक नई महत्वाकांक्षी और मजबूत एजेंडा का ऐलान करते हुए खुश हैं, जिसका फोकस चार प्रमुख क्षेत्रों पर है। इनमें समुद्री और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि एवं सुरक्षा, महत्वपूर्ण और नई टेक्नोलॉजी और मानवीय सहायता और आपातकालीन सहायता शामिल है। इसके तहत हम क्वाड की क्षमता को और बढ़ाएंगे ताकि क्षेत्र की सबसे जरूरी चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमारे संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग हो सके। बता दें कि इससे पहले शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमने उस हमले का करारा जवाब दिया है।

स्वामी मुद्रक प्रकाशक दिनेश एस त्रिखा द्वारा विभोरवार्ता आफॅसेट 2 स्टेशन रोड, सहारनपुर रोड देहरादून उत्तराखण्ड से मुद्रित कर 27 गुरूद्वारा रोड ज्वालापुर हरिद्वार उत्तराखण्ड से प्रकाशित। RNI NO.UTTHIN/2009/29251 प्रधान सम्पादक दिनेश एस. त्रिखा-9837012330 सम्पादक: विभोर त्रिखा-09927012330